हिन्दुस्तान 1936

ओलंपिक में व्यवहार

भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय खेल प्रशासन को विश्व स्तर पर अभी लंबा सफर तय करना है। मगर जिस तरह के विवाद या मामले ओलंपिक में कुछ भारतीयों के संबंध में उठे हैं, उनको देख चिंता स्वाभाविक है। महिलाओं की 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्द्धा के पहले ही दौर में हारने के बाद भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने पेरिस में अपने लिए बड़ी चिंताएं खड़ी कर ली थीं। यहां तक खबर चल पड़ी थी कि अंतिम पंघाल और उनके दल को पेरिस से निर्वासित कर दिया जाएगा, तीन साल के लिए प्रतिबंध लग जाएगा। बहरहाल, पंघाल पर यह आरोप तो लग ही गया कि उन्होंने अपना ओलंपिक मान्यता पत्र अपनी बहन को सौंप दिया था, जिन्हें ओलंपिक गांव के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने पकड़ लिया। भारतीय दल के लिए बड़े शर्म की स्थिति बन गई। इसमें कोई दोराय नहीं कि किसी खिलाड़ी के मान्यता पत्र पर केवल वही अधिकृत होता है, अगर वह अपना मान्यता पत्र किसी को देता है, तो वास्तव में पूरे खेल गांव की सुरक्षा पर सवाल लगाता है। अंतिम पंघाल से यही भूल हुई है, जिसका असर भारतीय ओलंपिक दल के सम्मान पर कमोबेश हुआ है।

गौर करने की बात है कि पंघाल अपना पहला ही मुकाबला बुरी तरह हार गई थीं और निराशा में उन्होंने खेल गांव छोड़ दिया था। यहां भी विवाद उठा कि उन्होंने खेल गांव छोड़कर अपनी बहन या कोच के होटल जाने की मंजूरी नहीं ली, हालांकि, बाद में पंघाल ने स्पष्ट किया कि वह बताकर ही गई थीं। होटल आकर उनकी तबियत खराब हुई और उन्होंने अपना मान्यता पत्र अपनी बहन को देकर खेल गांव से अपना सामान लाने भेज दिया। बेशक, यह तरीका गलत है, ओलंपिक के स्तर पर खिलाड़ियों को तमाम नियम-कायदों के प्रति सजग रहना चाहिए। वैसे जितनी लापरवाही खिलाड़ी की है, उतनी ही उसके कोच की भी है। वैसे, यहां तो खिलाड़ी के दो कोच सहयोगी बनने के बजाय स्वयं ही समस्या बन गए। भाषा की वजह से एक बैच लाकर से उनका विवाद हो गया। यहां भी पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुल मिलाकर, अंतिम पंघाल की पूरी टीम ही विवादों में आ गई और चर्चा चल पड़ी कि पूरी टीम को देश भेज दिया जाएगा। हालांकि, पंघाल प्रतिस्पर्द्धा से पूरी तरह बाहर हो गईं, तो उन्हें वैसे भी पूरी टीम के साथ स्वदेश लौटना ही था। अतः भारतीय दल की यह कोशिश होनी चाहिए कि अपने दल के सदस्यों का किसी भी तरह से अपमान न हो।

अंतिम पंघाल प्रकरण एक तरह से सबक है। हमारे देश के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उनकी टीम के सदस्यों को भी ओलंपिक या विदेश में लोकव्यवहार की पूरी सूचना नहीं है।

यह पूरा प्रकरण एक तरह से सबक है। हमारे देश के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि उनकी टीम के अन्य सदस्यों को भी ओलंपिक या विदेश में लोक-व्यवहार की पूरी सूचना नहीं है। क्या विदेश में किसी प्रतियोगिता में भाग लेने जाते समय दल के सदस्यों को प्रशिक्षित-सूचित नहीं किया जाता है? यह प्रबंधकों की भी गलती है। किसी भी स्थिति में खिलाड़ियों का तत्काल मार्गदर्शन करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश का प्रतिनिधित्व करना विदेश यात्रा का मौका मात्र नहीं है, इससे देश का सम्मान जुड़ा है। हमारे खिलाड़ियों को भाषा की समस्या आएगी, पर उन्हें पूरी सावधानी से किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाना होगा। कहीं न कहीं संदेश गया है कि भारतीय दल पूरी तरह से तैयार नहीं था। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, उसमें भी भारतीय खेल प्रबंधकों की बड़ी भूमिका है। काश! वे पूरी तरह सजग रहते, तो ओलंपिक में भारत की झोली इतनी हल्की न रहती।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 अगस्त, 1949

देश विभाजन स्वीकार्य नहीं

नई दिल्ली, ७ अगस्त। हिन्देशिया के प्रधानमन्त्री डा. मोहम्मद हट्टा हिन्देशियाई गोलमेज परिषद् के लिए हेग जाते हुए आज यहां पहुंचे। हवाई अड्डे पर भारत के प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डच राजदूत श्री लैम्मिंग, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर श्री अहमद इस्माइल, गवर्नर-जनरल के डिप्टी सैनिक सेक्रेटरी मेजर यूनुस खां और स्थानीय हिन्देशियाई व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। जैसे ही डा. हट्टा वायुयान से उतरे पत्र-प्रतिनिधियों और फोटोग्राफरों ने उन्हें घेर लिया। बाद में दोनों प्रधानमन्त्रियों ने एक साथ खड़े होकर मुस्कराते हुए अपना चित्र दिया। थोड़े अंतर पर एकत्रित भारी जनसमूह, जो डा. हट्टा के स्वागत के लिए एकत्रित हुआ था, यह सब देखकर खुश हो रहा था। डा. हट्टा ९ अगस्त तक नेहरूजी के अतिथि के रूप में यहां ठहरेंगे। डा. हट्टा के साथ हिन्देशिया के अर्थ मंत्री श्री ए. मरासिम और हिन्देशियाई जनतन्त्री सरकार के ४ अन्य सदस्य भी हैं।

कलकत्ते से गुजरते हुए डा. हट्टा ने प्रेस ट्रस्ट के प्रतिनिधि को बताया कि दिल्ली में रहते हुए मैं भारत की मदद से हिन्देशिया को समृद्धशाली बनाने के श्रेष्ठतम उपायों पर नेहरूजी के साथ विचार-विनिमय करूंगा। उन्होंने आगे कहा : हिन्देशिया की जनता राजनीतिक समझौते के लिए किसी भी रूप में देश का विभाजन न स्वीकार करेगी। हाल ही में एक प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ था, जिसमें दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि देश की अखंडता कायम रहनी ही चाहिए। गोलमेज परिषद् को राजनीतिक समझौते में सफलता प्राप्त करने का बहुत अच्छा अवसर है।

डा. हट्टा ने कहा कि अब जनतंत्रीय और इतर प्रदेशों के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है। अ-जनतंत्रीय प्रदेश में लगभग १५ रियासतें और एक दर्जन कबायली क्षेत्र सम्मिलित हैं। जनतन्त्री सरकार ने विधान-परिषद् की स्थापना तक के लिए इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा : हमें अब केवल यह समस्या हल करनी है कि हम राज्यों को अलग-अलग रखकर अथवा कई को साथ मिलाकर अपना संघ बनायें। हमने स्वीकार कर लिया है कि सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाये, क्योंकि हिन्देशिया इतना बड़ा देश है कि उसमें सुदृढ़ केन्द्र की स्थापना व्यावहारिक न होगी।

विनेश के विवाद से हमने जो सीखा

यहां स्कैन करें

नॉरिस प्रीतम | वरिष्ठ खेल पत्रकार

ऐसा नहीं है कि ये सबक सिर्फ ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ी सीखें, उनके साथ जाने वाले अधिकारियों का भी टेस्ट होना चाहिए, जिसे पास करके ही वे आयोजन में जा सकें।

विनेश फोगाट के साथ पेरिस में जो हुआ, उस घटना ने मुझे वर्ष 2015 की याद दिला दी। बात है लास वेगास में चल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप की। मैं वहां भारत में होने वाली रसलिंग लीग के लिए पहलवानों की तलाश में गया था। वहां मैंने पहली बार विनेश को करीब से देखा। वह शायद 19-20 साल की रही होंगी। चैंपियनशिप से दो दिन पहले वार्म-अप के दौरान विनेश का गट्टा मुड़ा और वह गिर पड़ीं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पट्टी-प्लास्टर कराकर वह वापस होटल लौटीं। डॉक्टरों की हिदायत थी कि उन्हें कम से कम दो दिन बिस्तर से नहीं उतरना है। मगर विनेश! वह तो दूसरे दिन प्लास्टर समेत रिंग में खड़ी थी। मैं हैरान था कि यह छोटी सी लड़की और इतनी हिम्मत!

खैर, वह चैम्पियनशिप में भाग नहीं ले पाईं, लेकिन उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर मेरे साथ-साथ उस समय के मशहूर छह बार के विश्व चैंपियन अमेरिका के जॉर्डन बरोज भी दंग रह गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस खिलाड़ी का ध्यान रखें, यह जरूर कुछ करेगी। मंगलवार को पेरिस में विनेश के प्रदर्शन को देखकर मुझे उसी अमेरिकी चैंपियन की बात याद आ रही थी। और अगले दिन जब विनेश की अयोग्यता का मामला सामने आया, तो सबसे पहले अगर किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने विनेश के लिए आवाज उठाई, तो वह जॉर्डन बरोज ही थे। उन्होंने विनेश को सिल्वर मेडल देने की मांग की, साथ ही यह भी सुझा दिया कि वजन के मामले में कम से कम एक किलोग्राम तक की छूट मिलनी चाहिए।

लास वेगास ही नहीं, उसके बाद मैंने विनेश की इवेंट रियो ओलंपिक में भी कवर की, जहां फिर उनके घुटने में चोट लगी, लेकिन इन सबके बीच वह भी महसूस किया कि वह बहुत ही दिलेर और हिम्मत वाली खिलाड़ी हैं। इतनी शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों के बाद शायद ही किसी खिलाड़ी ने इस तरह वापसी की हो और शुरुआती राउंड में ही ओलंपिक चैंपियन को मात दी हो, जैसा विनेश ने इस बार ओलंपिक में किया।

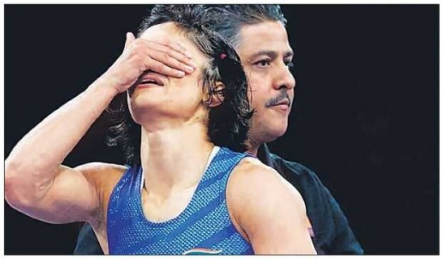

बहरहाल, विनेश की अयोग्यता घोषित होने के बाद भारत ही नहीं, पूरे विश्व के खेल जगत में तहलका मच गया है। अपने यहां सड़क से लेकर संसद तक कुश्ती शुरू हो गई है। कोई राजनीतिक दलों को दोषी मान रहा है, तो कोई खेल मंत्रालय को, तो कोई भारतीय ओलंपिक संघ को। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ को भी घेरने वाले कम नहीं हैं। हालांकि, विनेश खुद बहुत ही जज्बाती लड़की है और अयोग्य होने के बाद उन्होंने हजारों आंसू बहाए होंगे। मगर खेल के नियमों को ध्यान में रखते हुए, जिनसे वह बखूबी वाकिफ हैं, उन्होंने पहले खेलों के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाने की नहीं सोची। हालांकि, पूरे देश में चल रही बहस और पेरिस में मौजूद खेल अधिकारियों के दबाव के कारण अपील की गई होगी।

सवाल है कि यह हुआ कैसे? कौन इसका दोषी है या फिर कोई दोषी है ही नहीं? विनेश पहली दफा अंतरराष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं ले रही थीं और न ही उनके साथ गए हंगरी के वॉलर अकोस कोई मामूली कोच हैं। वह ख्याति-प्राप्त हैं और 2018 से विनेश के साथ हैं। उन्होंने 2011 में अपनी पत्नी को भी ट्रेनिंग देकर वर्ल्ड चैम्पियन बनाया था। जाहिर है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी को नियम नहीं पता होगा। तब भी यदि विनेश मुकाबले की सुबह तय वजन से अधिक पाई गईं, तो कहीं न कहीं चूक तो हुई है। मगर इसे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र या घरेलू साजिश नहीं कहा जा सकता। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इसी तरह की बातें चल रही हैं।

जो हुआ, वह गलत हुआ, लेकिन अब ऐसा क्या किया जाए कि भविष्य में इस तरह की या इससे मिलती-जुलती कोई घटना न हो। पेरिस को ही अगर लें, तो कहा जा रहा है कि विनेश को फाइनल में अपने प्रतिद्वंद्वी को वाकओवर दे देना चाहिए था, ताकि कम-से-कम सिल्वर तो मिल जाता। मगर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वजन करवाने से पहले खिलाड़ी का मेडिकल भी होता है, जो विनेश करवा चुकी थीं, और वजन ज्यादा पाए जाने के बाद वाकओवर नहीं दिया जा सकता। हां, अगर उनके साथ गए अधिकारी और सहायक स्टाफ इस बात को पहली रात ही भांप लेते, तो शायद अस्वस्थता को कोई पुख्ता कारण दिया जा सकता था। मगर इसके लिए अधिकरियों को बहुत रणनीतिक होना पड़ेगा। खिलाड़ियों को भी ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार करना होगा और यह सिर्फ पहलवानी में ही नहीं, सभी खेलों में करना होगा।

हालांकि, एक दिक्कत यह है कि अपने देश में लोग आमतौर पर गलती से सबक सीखने से कतराते हैं। अक्सर हमारे खिलाड़ी डोपिंग में फंसे हैं, लेकिन हमने कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया। ताजा प्रकरण के बाद ही हमें अपने कोच, खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देनी होगी, साथ ही खिलाड़ियों को भी खेलों के नए नियम बताने होंगे। तौर-तरीका और अनुशासन सिखाना होगा। पेरिस में ही एक खिलाड़ी अपनी बहन को अपने कार्ड से ओलंपिक खेल गांव में भेजती हुई पकड़ी गई। गनीमत है कि पुलिस ने बहन को छोड़ दिया और खिलाड़ी को वापस भारत भी भेज दिया गया है। मगर विदेश में होने वाला यह घोर अपराध है और शर्मनाक भी।

ऐसा नहीं है कि ये सबक सिर्फ ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ी सीखें, बल्कि हर उस खिलाड़ी को यह जानना चाहिए, जो किसी भी राष्ट्रीय स्पर्द्धा का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय दलों के साथ जाने वाले अधिकारियों का भी टेस्ट होना चाहिए, जिसे पास करके ही उनको सीमा पार जाने की इजाजत मिलनी चाहिए।

होना यह भी चाहिए कि हर वह अधिकारी, जो किसी खेल-दल के साथ विदेश जाए, वह उस खेल का कम से कम राज्य स्तर पर चैंपियन रहा हो। मुझे याद है, सन् 1978 के बैंकॉक एशियाई गेम्स में भारत की एंजेल मैरी पेंटाथलॉन स्पर्द्धा में हिस्सा ले रही थीं और काफी अच्छा कर रही थीं। मगर एथलेटिक्स महासंघ का एक वरिष्ठ अधिकारी गुस्से में था कि वह इतनी स्पर्द्धाओं में हिस्सा क्यों ले रही हैं? असल में, उस अधिकारी को पता ही नहीं था कि पेंटाथलॉन में पांच खेल होते हैं और जब मैरी को मेडल मिला, तो वही अधिकारी सबको बता रहे थे कि खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं! जब तक ऐसे अधिकारी साथ जाएंगे, भारतीय खेल का भला नहीं होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

बुद्धदेब भट्टाचार्य : एक कवि हृदय राजनेता का चले जाना

यहां स्कैन करें

शंभूनाथ शुक्ल | वरिष्ठ पत्रकार

वर्ष 2001 की जनवरी की एक सुबह मेरे पास पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य के सचिव सत्य प्रकाश का फोन आया कि आज शाम मुख्यमंत्री आप से मिलेंगे। शाम पांच बजे जब मैं राइटर्स बिल्डिंग पहुंचा, तब मुख्यमंत्री कक्ष में जाने के पहले एक सिपाही ने परिचय पूछा और अनुमति दे दी। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई बंदिश नहीं। बैठक में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आ गए। सिर के सारे बाल सफेद। सफेद धोती-कुर्ता तथा कोल्हापुरी चप्पल। मुख्यमंत्री टूटी-फूटी हिंदी ही बोल पाते थे, अलबत्ता बांग्ला में निपुण थे। मैं उनसे हिंदी में सवाल पूछता गया और वह जवाब बांग्ला व अंग्रेजी में देते गए। एक घंटे चले इंटरव्यू में वह अपने प्रदेश के औद्योगीकरण के लिए ही ज्यादा चिंतित दिखे।

एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री द्वारा कारखाने फिर खुलवाने और पूंजी को न्योतने के उनके प्रयास आश्चर्यचकित कर देते थे। ये वही बुद्धदेब बाबू थे, जो अपने शुरुआती दिनों में पूंजीपतियों के विरोधी थे, मगर 1991 के बाद हुए सोवियत संघ के विघटन ने बाजार, पूंजी और मजदूर की परिभाषा ही बदल दी। यह बात तमाम कम्युनिस्ट समझ नहीं पाए थे, पर बुद्धदेब शायद समझ गए थे। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु लगातार 24 वर्ष मुख्यमंत्री रहे थे। वैसे, बुद्धदेब भट्टाचार्य को उप-मुख्यमंत्री बनाकर सीपीएम उनकी ताजपोशी की तैयारी पहले से कर रही थी। तब स्वयं बुद्धदेब भी असमंजस में थे कि ज्योति बसु जैसे वटवृक्ष का उत्तराधिकार वह संभाल पाएंगे या नहीं। खैर, मौका आया और उन्होंने चुनौती स्वीकार की। प्रदेश से बेरोजगारी खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में उद्योगों को बढ़ावा देने की ठानी। यह आसान नहीं था, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने उद्योगों को ध्वस्त कर दिया था। वे उद्योगपतियों से मुनाफे में हिस्सा मांगते और मजदूरों में कामचोरी की आदत डालते थे। मजदूर संघ कारखानों के बजाय व्यवसाय (ट्रेड) बढ़ाने के पक्षधर थे, जबकि रोजगार व वृद्धि के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जरूरी हैं। बुद्धदेब ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने राज्य की सुस्त नौकरशाही को दुरुस्त करने की कोशिश की।

वर्ष 2000 की 6 नवंबर को बुद्धदेब ने प्रदेश की कमान संभाली थी और 2 मई, 2001 को बेलाला जाकर पैटन टैंक (पानी की टंकियां बनाने वाला एक ब्रांड) की एक नई यूनिट का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्पादकता व निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया। राज्य के औद्योगिक विकास पर जोर देने की उनकी पहल चर्चा में आने लगी। ध्यान रहे, साल 1966 से पश्चिम बंगाल में जब से नक्सली गतिविधियां बढ़ी थीं, वहां के उद्योगपतियों ने कोलकाता छोड़ना शुरू कर दिया था। बुद्धदेब ने मुख्यमंत्री के रूप में माहौल को बदलना शुरू किया। उनकी अपनी लोकप्रियता भी बढ़ी, उनके नेतृत्व में वामपंथियों ने साल 2001 और 2006 में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। हरनेता का एक समय आता है, जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। सिंगुर व नंदीग्राम आंदोलन के समय बुद्धदेब के साथ ही वामपंथी शासन की भी उल्टी गिनती तेज हो गई थी। साल 2011 में पश्चिम बंगाल ने ही नहीं, बल्कि बहुत हद तक देश ने भी अपने एक भद्रलोक-प्रतिनिधि मुख्यमंत्री को पद से विदा कर दिया।

मार्क्सवाद को उदारवाद के साथ-साथ थामे हुए उनकी सोच में लोक कल्याण की भावना थी। वह वामपंथी कम, बांग्ला भद्र मानुस ज्यादा थे।

नामचीन बांग्ला कवि सुकांतो भट्टाचार्य के भतीजे बुद्धदेब का एक रूप उनका नाटक और कला के प्रति अगाध प्रेम भी था। 1992 में जब बाबरी ध्वंस हुआ, तब उन्होंने *दुस्समय* नाम से नाटक लिखा था, जो राजनीतिक छद्म और कट्टरता पर प्रहार करता है। इसका जब मंचन हुआ, तब दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए थे। उन्होंने कापका की रचना *मेटामारफोसिस* का बांग्ला अनुवाद *पोका* के नाम से किया है। उन्होंने एक प्रबंध काव्य लिखा है *पूड़े जाय जीवन नश्वर*। वह मृत्युपर्वत 'नंदन' जाते रहे, जो कोलकाता का सांस्कृतिक केंद्र है।

मार्क्सवाद को उदारवाद और पूंजीवाद के साथ-साथ थामे हुए उनकी सोच में लोक कल्याण की भावना थी, वह अपनी सोच में वामपंथी कम और बांग्ला भद्र मानुस ज्यादा थे। उनकी लोकप्रियता उनके दल से परे भी पसरी हुई थी, इसीलिए उनके निधन की सूचना आते ही पूरा बंगाल शोक में डूब गया। वह पिछले 13 वर्ष से सक्रिय राजनीति से दूर थे, पर लोग इस आधुनिक कॉमरेड को भूले नहीं थे और न भूल पाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

भारतीय मानस की खूबियां

भारत के लोगों की, यहां तक कि अबोध जनता की भी, यह विशेषता है कि वे सदियों के प्रशिक्षण के कारण आंतरिक वास्तविकताओं के अधिक निकट हैं और अधिक सरलता के साथ ईश्वर व पारलौकिक जीवन के जीवंत दर्शन से जुड़ जाते हैं, बनिस्बत किसी अन्य जगह के आम लोगों या सुसंस्कृत ऊंचे स्तर के लोगों के, अन्यथा कहां बुद्ध के ऊंचे, आंतर्संयमी और कठिन उपदेश लोक मानस को इतनी शीघ्रता से ग्रसित कर पाते? कहां तुकाराम, रामप्रसाद, कबीर और सिख गुरुओं के न केवल गीत व भावप्रवण भक्ति से भरे तमिल संतों के आलाप, बल्कि उनके उदात्त आध्यात्मिक विचार इतनी शीघ्र प्रतिध्वनि पाकर एक लोकप्रिय धार्मिक साहित्य का निर्माण कर पाते? समूचे राष्ट्र की यह सशक्त पारगम्यता या आध्यात्मिक प्रकृति से समीपता परम आध्यात्मिक संस्कृति के लक्षण और परिणाम हैं।

पश्चिम की मनोवृत्ति बहुत समय से पूरी मानवता के लिए एक ही धर्म के आक्रामक और बिल्कुल तर्क-विरुद्ध विचार को पोषित करती आई है, एक ऐसा धर्म, जो अपनी संकीर्णता, धर्मसिद्धांतों की एक श्रेणी, एक उपासना पद्धति, अनुष्ठानों की एक प्रणाली, विधि-निषेधों के एक विन्यास, एक धार्मिक अध्यादेश के बल पर सार्वभौम हो। वह संकीर्ण असंगति एक सच्चे धर्म के रूप में इठलाती फिरती है, जिसे यहां लोगों द्वारा उत्पीड़ित किए जाने के डर से और दूसरे लोकों में ईश्वर द्वारा आध्यात्मिक अस्वीकारया भयंकर दंड दिए जाने के डर से सभी को स्वीकार करना चाहिए। मानव तर्कहीनता का यह विकृत सृजन भारत के स्वतंत्र और लचीले मानस को कभी दृढ़तापूर्वक पकड़ नहीं पाया है।

आदमियों में हर जगह एक जैसी मानवीय कमजोरियां होती हैं और विशेष रूप से धार्मिक रीति-रिवाजों के मामले में भारत में भी असहिष्णुता और संकीर्णता रही है और है।... परंतु यहां इन चीजों का उतना अनुपात नहीं हो पाया, जितना यूरोप में हो गया था। यहां अधिकतर असहिष्णुता खंडन-मंडन के छोटे-मोटे स्वरूपों या जाति-बहिष्कार तक सीमित रही है। बहुत ही कम उन्होंने रेखा पार करके बर्बर उत्पीड़न के उन स्वरूपों को अपनाया है, जिन्होंने यूरोप के धार्मिक इतिहास के पटल पर एक लंबा और वीभत्स दाग अंकित कर दिया है।

भारतीय धर्म ने हमेशा यह महसूस किया कि चूंकि मस्तिष्क, प्रवृत्तियां और लोगों के बौद्धिक संबंध अपनी विविधता में निरस्सीम हैं, इसलिए व्यक्ति को पूजा की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

भारत में सदैव ही एक उच्चतर और अधिक पवित्र आध्यात्मिक बुद्धि की रक्षाकारी सूझ-बूझ क्रियाशील रही है, जो अपना प्रभाव आम जनता की मनोवृत्ति पर डालती रही है। भारतीय धर्म ने हमेशा यह महसूस किया कि चूंकि मस्तिष्क, प्रवृत्तियां और लोगों के बौद्धिक संबंध अपनी विविधता में निस्सीम हैं, इसलिए व्यक्ति को परमात्मा के प्रति अपने रवैये में विचार और पूजा की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

श्री अरविंद

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

जब ट्रैक्टर आए, तो लोगों ने सोचा कि किसान बेकार हो जाएंगे। जब कंप्यूटर आए, तो सोचा कि इंजीनियरों की जरूरत नहीं रह जाएगी। डिजिटलीकरण के बारे में इसी तरह सोचा गया, पर हर युग हमें सशक्त बनाता है, हमारी उत्पादकता बढ़ाता है।

फोगाट के अयोग्य होने में षड्यंत्र की बू

विनेश फोगाट असली योद्धा हैं। सड़क से लेकर खेल के मैदान तक अपनी लड़ाई लड़ने और बड़े-बड़े बाहुबलियों से लेकर महाबलियों तक के छक्के छुड़ाने में सक्षम हैं। उन्होंने अपनी ताकत देश और दुनिया के सामने सिद्ध कर दी है। अब चाहे कोई बाहुबली हो या महाबली, वे विनेश के सामने बौने ही रहेंगे। मुझे तो पूरा संदेह है कि विनेश के साथ कुछ-न-कुछ षड्यंत्र जरूर हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले उनके दुनिया के बड़े-बड़े महाबलियों को पछाड़कर फाइनल में पहुंचने की खबर से कई लोगों की छाती पर सांप लोटने लगा था। कुछ लोगों की तो प्रतिक्रियाओं से भी यह जाहिर हो रहा था, जैसे वे बहुत खिसियाए हुए हैं। ऐसे में, विनेश को पदक से वंचित किया जाना भारत के लोगों की नजर में ओलंपिक के इतिहास का एक कलंकित अध्याय तो रहेगा ही, लेकिन अपने ही देश में विनेश के साथ जैसा दुर्व्यवहार हुआ है, वह भी कम शर्म की बात नहीं मानी जाएगी। विनेश के साथ किए गए पाप से कोई भी बरी नहीं हो सकता- न तो कोई संबद्ध व्यक्ति और न ही कोई संबद्ध संस्था। हर देश की एक अंतरात्मा होती है और भारत की अंतरात्मा विनेश फोगाट के साथ है।

अभिरंजन कुमार, टिप्पणीकार

चैंपियन हैं वह

कई तथाकथित स्वघोषित देशभक्त लोग इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि विनेश फोगाट ओलंपिक से बाहर हो गईं और भारत अब इस स्पर्द्धा में सोने से महरूम हो गया! लानत है ऐसे लोगों पर। विनेश फोगाट फाइनल मुकाबला खेलतीं, तो बहुत मुमकिन था स्वर्ण पदक आता और वह पदक भारत के नाम होता, इससे विश्व पटल पर भारत का ही ओहदा बढ़ता। असल में, वे लोग इसलिए खुश हैं, क्योंकि फोगाट एक किसान की बेटी हैं, जिन्होंने सड़कों पर आंदोलन किया है। ऐसे लोग भूल गए हैं, बाकी मेडल भी किसान के बेटे-बेटियां ही ला रहे हैं। वे यह समझ लें कि विनेश फोगाट चैंपियन थीं, हैं और रहेंगी, क्योंकि उन्होंने साजिश रचने से पहले ही अपना गोल्ड मेडल जीत लिया था, जब विश्व के नंबर वन पहलवान को धराशायी किया और एक ही दिन में तीन-तीन विश्वस्तरीय पहलवानों को धूल चटाने में सफलता हासिल की। इस गोल्डन गर्ल को अखाड़े में दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती थी, इसलिए उसे अखाड़े से बाहर हराने की साजिश रची गई और उनको सोने का एक तमगा हासिल करने से रोक दिया गया। फोगाट सिर्फ एक तमगा ही हासिल नहीं कर सकीं, बाकी अखाड़े की अपराजेय चैंपियन वही हैं। वह भारत का गौरव और इसकी आन-बान-शान हैं।

ओम के बायतु, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

विनेश फोगाट

साजिश कहने वाले कायदा नहीं जानते

विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य होने पर बहुत से लोग राजनीति कर रहे हैं और तरह-तरह की बातें बोली जा रही हैं। कोई इसको साजिश बता रहा है, तो कोई कुछ और। मगर कुछ कहने से पहले हमें इसके पीछे की कहानी थोड़ी जान लेनी चाहिए। विनेश फोगाट का सामान्य वजन 57 किलोग्राम के करीब है। वह इस वर्ग में पहले खेल भी चुकी हैं। कोई खिलाड़ी तीन-चार किलो वजन आसानी से घटा पाता है, इसलिए वह 53 किलोग्राम में भी खेलती थीं। मगर इस बार उन्होंने सात किलो वजन घटाकर 50 किलोग्राम में भाग लिया। वह सब इसलिए करना पड़ा, क्योंकि विनेश 29 साल की हो चुकी हैं और अगले ओलंपिक तक वह 33 की हो जाएंगी। ऐसे में, नए-नए खिलाड़ी आ जाते और मुकाबला कड़ा होता जाता।

सेमीफाइनल से पहले उसका वजन 49.9 किलोग्राम था। और वह तब था, जब वह कई दिनों से बहुत कम खा रही थीं और पानी भी बहुत कम पी रही थीं। फिर उन्होंने तीन सफल मैच खेले, तो संभवत एनर्जी लॉस हुआ होगा, जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें कुछ डाइट लेनी पड़ी होगी। इससे उनका वजन 2.8 किलोग्राम बढ़ गया। इसे कम करने के लिए उन्होंने रात भर मेहनत की। सुबह तक 2.7 किलोग्राम तक वजन कम भी कर लिया, लेकिन 100 ग्राम से चूक गईं। साक्षी मलिक, जो खुद पहलवान हैं, बताती हैं कि उन्होंने खून तक निकलवाया था, ताकि वजन घट सके। जाहिर है, उन्होंने ऐसा कुछ खा लिया कि वजन इतना ज्यादा बढ़ गया।

आपको ध्यान हो कि जब विनेश ने 50 किलोग्राम वजन में भाग लेने का निर्णय लिया था, तो कई कुश्ती के जानकार कह रहे थे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जाहिर है, इसकी वजह थी। निस्संदेह, विनेश फोगाट बहुत ही जज्बे वाली खिलाड़ी हैं और कई मौकों पर उन्होंने खुद को साबित किया है, लेकिन अभी साजिश की जो बात की जा रही है, वह गले नहीं उतरती। इतना ही नहीं, जो वह कह रहे हैं कि सिर्फ 100 ग्राम की वजह से अयोग्य ठहरा दिया, उनको समझ लेना चाहिए कि यह ओलंपिक है, कोई गांव की प्रतियोगिता नहीं कि चलो थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे कर देते हैं। इसके अपने नियम-कानून हैं, जिसे सभी खिलाड़ियों को मानना पड़ता है। इसमें दुनिया भर के बेहतरीन रेफरी बुलाए जाते हैं। सब कुछ की वीडियोग्राफी होती है, इसलिए अनर्गल आरोप लगाना बंद कीजिए। हर किसी को दुख है फोगाट के अयोग्य होने पर। मगर क्या कर सकते हैं। भड़काऊ बातें करके खिलाड़ियों का ध्यान न भटकाइए, बल्कि उनका हौसला बढ़ाइए।

संदीप बल्हारा, टिप्पणीकार

ज्यादातर सैन्य तख्तापलट लोकतंत्र की बहाली के नाम पर ही किए जाते हैं। -एडुआर्डो गेलियानो

वैश्विक कंसल्टेंट फर्म बेन ऐंड कंपनी और लाइफस्टाइल से जुड़े एक प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट का यह कहना कि भारत वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड्स का गंतव्य बन रहा है, अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक संकेत तो है ही, उपभोक्ताओं के बदलते मिजाज को भी दर्शाता है।

पैसा, मिजाज और वैश्विक ब्रांड

वैश्विक कंसल्टेंट फर्म बेन ऐंड कंपनी और लाइफस्टाइल से जुड़े एक प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की हालिया रिपोर्ट का यह बताना कि दुनिया के शीर्ष पचास लाइफस्टाइल ब्रांड में से करीब नब्बे फीसदी भारत में मौजूद हैं, वैश्विक लाइफस्टाइल बाजार में भारत की दमदार उपस्थिति को तो दर्शाता ही है, इससे देश के उपभोक्ताओं के मिजाज में आ रहे बदलाव को भी समझा जा सकता है। जब लोगों के पास पैसा आता है, तो वे लग्जरी उत्पादों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे उनमें बड़े ब्रांड की तलाश की प्रवृत्ति पैदा होती है। वैश्विक रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत का लग्जरी उत्पाद बाजार 2030 तक अपने वर्तमान आकार से साढ़े तीन गुना तक बढ़ सकता है, जिसका श्रेय देश के बढ़ते मध्यवर्ग के साथ स्टार्टअप और ई-कॉमर्स संस्कृति को भी जाता है, जिसने छोटे व मंझोले शहरों तक पहुंच बनाई है। ध्यान रहे कि लाइफस्टाइल उत्पाद जीवन की बुनियादी जरूरतों से नहीं, बल्कि कुछ हद तक विलासिता से जुड़े होते हैं। जाहिर है कि भारत अगर वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड के केंद्र के रूप में उभर रहा है, तो इसकी एक वजह देश में समृद्ध लोगों की बढ़ती संख्या भी है, जिसकी पुष्टि आयकर रिटर्न भरने वालों की बढ़ती संख्या से भी होती है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब साढ़े सात फीसदी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त, अन्य एशियाई देशों की तुलना में यहां महंगाई काबू में होना, फैशन को लेकर बढ़ता आकर्षण, बाजार में युवा खरीदारों की बढ़ोतरी और ब्रांड के उत्पादों को लेकर बढ़ती दिलचस्पी भी इसके कारण हैं। दरअसल, ई-लाइफस्टाइल बाजार ने भी ब्रांडेड उत्पादों तक लोगों की पहुंच को बढ़ाया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान तेज डिलिवरी और आसान रिटर्न के अलावा सोशल मीडिया से होने वाली खोजों का भी है। तमाम वैश्विक अनिश्चितताओं व मंदी की आशंकाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अगले कुछ वर्षों में इसके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। ऐसे में, बड़े वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड्स का भारत की ओर देखना स्वाभाविक ही है। हालांकि, अमेरिका, चीन व जर्मनी जैसे वैश्विक बाजारों की ई-लाइफस्टाइल में पैठ 35 फीसदी से ज्यादा है। भारत में यह 2023 से 2028 के बीच 13 से बढ़कर 18-22 फीसदी होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष साठ से भी ज्यादा वैश्विक ब्रांड्स देश में लॉन्च हुए या उनकी योजना बनाई गई। करीब पचास फीसदी वैश्विक ब्रांड्स का भारत में राजस्व पहले ही तीन करोड़ डॉलर से ज्यादा है। ऐसे में, भारत में प्रवेश को लेकर शीर्ष वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड्स में जो होड़ दिख रही है, वह देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत ही है।

पाकिस्तान में भी आसार अच्छे नहीं हैं

बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान में भी तख्तापलट का इतिहास रहा है। रावलपिंडी में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में हजारों लोग बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरकर शहबाज शरीफ को धमका रहे हैं कि उनका हश्र हसीना से बुरा होगा। बलूचिस्तान के भी बुरे हाल हैं। कहीं अब पाकिस्तान की बारी तो नहीं?

मरियाना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

नौ जुलाई, 2022 की एक बेहद दिलचस्प तस्वीर है, जिसमें श्रीलंका के प्रदर्शनकारी वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भाग जाने के बाद कोलंबो स्थित राष्ट्रपति निवास के स्वीमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाद में राष्ट्रपति भवन को लूटने के बाद उसमें आग भी लगा दी थी। इस हफ्ते दुनिया ने देखा कि किस तरह बांग्लादेशी छात्रों ने अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के आधिकारिक आवास पर धावा बोल दिया और वहां काफी लूटपाट की। हालांकि तब तक वह मुल्क छोड़कर भारत भाग चुकी थीं। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी उनके बिस्तर पर भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ अन्य लोग रसोईघर में घुसकर जो भी मिला, उसे खाते दिखे।

क्या दक्षिण एशिया के इस क्षेत्र में तीसरी बार भी ऐसी घटना होगी? क्या अगला नंबर पाकिस्तान का है? यह सवाल पूर्व मंत्री और सांसद सैयद मुशाहिद हुसैन ने पूछा, जो पीएमएल (एन) के सदस्य हैं और कई दशक पहले ढाका में रह चुके हैं। मुशाहिद हुसैन यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में भी कई आंदोलन चल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से रावलपिंडी शहर के मुख्य केंद्र मुर्री रोड पर सड़क को बंद करके जमात-ए इस्लामी का धरना चल रहा है, जहां हजारों लोग बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ सरकार बेरोजगारी, मुद्रास्फीति का तत्काल समाधान करे और विशेष रूप से नागरिकों के बिजली बिलों में वृद्धि को कम करे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जमात-ए इस्लामी के नवनिर्वाचित प्रमुख हाफिज नईमुर्रहमान ने शहबाज शरीफ को चेतावनी दी कि यदि वह उनकी पार्टी की मांगें नहीं मानेंगे, तो उनका हश्र शेख हसीना से भी बुरा होगा, क्योंकि उन्हें मुल्क छोड़ने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी।

इस बीच बलूचिस्तान के एकमात्र बंदरगाह शहर ग्वादर सहित कई अन्य शहरों में पिछले दो हफ्ते से धरना-प्रदर्शन जारी है। रावलपिंडी के विरोध प्रदर्शन के विपरीत बलूचिस्तान में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं, जहां गोलीबारी में कई लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए और कई लोगों को सरकारी एजेंसियों द्वारा उठा लिया गया। इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व एक युवा बलोच महिला डॉ. महरंग बलोच कर रही हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने उस पुरानी बलोच परंपरा को तोड़ा है, जिसमें महिलाओं को घरों तक ही सीमित रखा जाता था। वह अब नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले हजारों पुरुष एवं महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। हजारों बलोच नागरिक मांग कर रहे हैं कि पुरुषों को लगातार सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाकर गायब किया जाना हमेशा के लिए बंद हो। गौरतलब है कि उठाकर गायब किए जाने वाले लोगों में ज्यादातर युवा हैं। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि सभी चेकपोस्ट हटा लिए जाएं, ताकि लोग आसानी से आ-जा सकें। इसके अलावा बलोच प्रदर्शनकारियों की सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, न कि दूसरे प्रांतों को भेजे या निर्यात किए जाएं।

इस बीच उत्तरी इलाकों में भी लोग कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने काराकोरम हाईवे को जाम कर दिया है, जो खुंजराब दर्रे के माध्यम से पाकिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। वे संघीय राजस्व बोर्ड और पाकिस्तान सीमा शुल्क के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में व्यापारियों पर कर लगाया है। पाकिस्तान से चीन जाने के इच्छुक कई विदेशी भी यहां फंस गए हैं और उन्हें प्रदर्शनकारियों के साथ बैठे देखा जा सकता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के हर हिस्से में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं।

बांग्लादेश में जारी घटनाएं इस क्षेत्र एवं पश्चिम में अब भी सुर्खियों में हैं। इसलिए पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों कई मुस्लिम देश गंभीर राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद कहते हैं, 'ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे सत्ता बरकरार रखने के लिए लोगों से शक्ति प्राप्त करने के बजाय सेना या सुरक्षा संगठनों पर ज्यादा निर्भर हैं। इससे उनकी प्रगति में बाधा आई है और वे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने के लिए प्रमुख वैश्विक शक्तियों पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं।'

बांग्लादेश में जारी उथल-पुथल में एक और महत्वपूर्ण बात यह उभर कर आई है कि क्षेत्रीय और पड़ोसी देशों ने ढाका के साथ अपनी विदेश नीति को किस तरह आगे बढ़ाया है। भारत को शेख हसीना का एक मजबूत सहयोगी माना जाता है, लेकिन ढाका स्थित सैन्य सूत्रों के हवाले से रॉयटर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली ने शेख हसीना से कहा कि उन्हें भारत में अस्थायी तौर पर ही रहने का ठिकाना मिल सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका कारण यह है कि ढाका की ओर से मांग की जा रही है कि शेख हसीना को उनके मुल्क वापस भेजा जाए। जाहिर है, भारत बांग्लादेश और वहां बनने वाली नई सरकार के साथ अपने भावी संबंधों का भी आकलन करना चाहेगा और वह नहीं चाहेगा कि उसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री का पक्ष लेते हुए देखा जाए। हालांकि पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति का झुकाव व्यक्ति विशेष यानी शेख हसीना के प्रति है, न कि एक सरकार का दूसरे सरकार के प्रति।

प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ढाका में नई अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लोगों के लिए सद्भावना संदेश भेजा है, जबकि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर इसे बांग्लादेश का घरेलू मुद्दा मानकर चुप्पी साध रखी थी। पाकिस्तान ने अपने संदेश में कहा कि वह बांग्लादेश के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है तथा ईमानदारी से शांतिपूर्ण एवं शीघ्र सामान्य स्थिति बहाली की उम्मीद करता है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी तख्तापलट और सैन्य शासन का इतिहास रहा है। हालांकि छात्र नेताओं के बयानों से यह साफ है कि वे सैन्य शासन का विरोध करेंगे और बांग्लादेश में जनता की ताकत ही शासन करेगी।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

वारेन बफे

समय सबसे मूल्यवान है। इसका प्रबंधन करना चाहिए। आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा, और जब तक आप 'नहीं' कह पाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।

असल संपत्ति तो आप ही हैं, खुद में निवेश करें

जीवन की सफलता को केवल धन के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता और न ही कभी ऐसा करना चाहिए। सिर्फ पैसा ही सफलता का पर्याय नहीं होता। आप सफलता को चाहे जैसे परिभाषित करें, इसमें व्यक्तिगत विकास ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको समय के साथ खुद को बेहतर बनाने का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए सबसे बड़ा निवेश जो आप कर सकते हैं, वह अपने आप में निवेश करना है। अपने आप में निवेश करने का मतलब है-अपना ख्याल रखना। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कार है। निस्संदेह आप इसका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, समय-समय पर उसके रखरखाव पर खर्चा करेंगे, हमेशा सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। अब जरा इस पर भी विचार करें कि आपके पास केवल एक दिमाग और एक शरीर है। जाहिर है, आप जीवन भर इन्हें भी दुरुस्त रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इनकी हरसंभव देखभाल करेंगे, उस पर जो खर्च करना होगा, करेंगे। यानी अपने सभी प्रयासों से आप समय के साथ अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की असल संपत्ति तो वह स्वयं ही है, इसलिए स्वयं को दुरुस्त और सुरक्षित रखें।

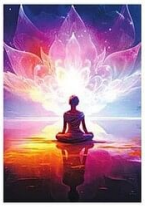

इस धरती पर आपके पास जितना समय है, वह वह निर्धारित करता है कि आप अपने ज्ञान, कौशल और धन को कितना बढ़ा सकते हैं। केवल जीवित रहने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे हैं। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है, इसलिए हमें प्रभावी ढंग से इसका प्रबंधन करना चाहिए। आपको अपने समय पर नियंत्रण रखना होगा, और जब तक आप 'नहीं' कह पाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप दूसरे को अपने जीवन में अपना एजेंडा निर्धारित नहीं करने दे सकते। महत्वपूर्ण कार्यों में समय लगाने से आपकी प्रभावशीलता कई गुना बढ़ती जाएगी। इसलिए सर्वश्रेष्ठता पर ध्यान दें, बाकी को भूल जाएं। सफल लोगों और वास्तव में सफल लोगों के बीच अंतर यह है कि वास्तव में सफल लोग 'न' कहना जानते हैं। हम सभी कुछ लोगों और कुछ अवसरों के लिए 'हां' कहते हैं। आप किसे 'हां' कहते हैं, यह बहुत मायने रखता है। जीवन में सफलता के लिए अपने से बेहतर लोगों के साथ साझेदारी करने की पूरी कोशिश करें। अपने से बेहतर लोगों के साथ घूमना श्रेष्ठ होता है। ऐसे सहयोगियों को चुनें, जिनका व्यवहार आपसे बेहतर हो, तभी आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम किसके साथ जुड़ते हैं और किसका आदर करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह इस बात का प्रतिबिंब होता है कि हम कौन हैं और क्या बनने जा रहे हैं। हम किसके साथ जुड़ते हैं, इसका सीधा असर हमारी प्रतिष्ठा पर पड़ता है। प्रतिष्ठा ही जीवन को मूल्यवान बनाती है। याद रखें, प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इसे धूमिल होने में सेकंड भी नहीं लगता।

ईमानदारों की संगति करें

सूत्र

जीवन में ईमानदार लोगों की संगति बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदारी के महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है। ईमानदारी एक बहुत महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे दूसरों की ईमानदारी महत्वपूर्ण है, वैसे ही स्वयं के प्रति ईमानदार होना भी महत्वपूर्ण है।

दूसरा पहलू

टोक्यो व बीजिंग ओलंपिक की तरह पेरिस ओलंपिक में ज्यादातर टीमों ने कोविड को कोई तवज्जो नहीं दी है, परंतु नीदरलैंड अपवाद है।

पेरिस ओलंपिक में हाथ नहीं मिला रहे डच खिलाड़ी

नीदरलैंड के हॉकी खिलाड़ी डुको टेलजेनकैंप अपनी स्पष्ट रणनीति के साथ पेरिस ओलंपिक में आए हैं। वह कहते हैं कि हमारा मकसद अगले बढ़ना है और यह दृढ़ता जरूरी है। ओलंपिक में हिस्सा ले रहे नीदरलैंड के खिलाड़ी और स्टाफ को स्पष्ट निर्देश है कि किसी से हाथ नहीं मिलाना है और गले भी नहीं लगना है। सिर्फ मुट्ठी बांधकर रहना है। डच दृष्टिकोण की अपनी एक अलग विरासत है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में कोरोना वायरस को बहुत तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोरोना महामारी के दौरान हुए ओलंपिक के पिछले दो संस्करणों-टोक्यो ओलंपिक और बीजिंग विंटर ओलंपिक में खिलाड़ियों पर कई प्रतिबंध लगे थे। लेकिन इस बार पेरिस में प्रशंसकों से खचाखच भरे स्टेडियमों में ऐसा कुछ नहीं है।

सॅरी स्मिथ

टोक्यो में हर चौथे दिन, तो बीजिंग में प्रतिदिन कोरोना जांच होती थी। यदि कोई पॉजिटिव मिलता, तो उसे एकांतवास में रख दिया जाता था। खिलाड़ियों को सिर्फ स्पर्धा के दौरान ही मास्क हटाने की अनुमति होती थी। मगर पेरिस में कोरोना को लेकर कोविड जांच की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कुछ सतर्कताएं बरती जा रही हैं। अमेरिका की ओलंपिक और पैरालंपिक समिति का नारा है, 'सदैव आपको स्वर्ण से दूर न रखें'। ऑस्ट्रेलिया की टीम के डॉ. कैरोलिन ब्रॉडरिक बताते हैं कि हम जांच करने के लिए मशीन भी अपने साथ लाए हैं। फ्रांस में यदि कोई खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे एन-95 मास्क लगाने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह खेल से बाहर हो गया है।

नीदरलैंड के हॉकी खिलाड़ी जॉरिट क्रून ने कहा कि वे खिलाड़ियों के बीमार होने की वजह से पदक जीतने का एक फीसदी मौका भी नहीं गंवाना चाहते। पदक जीतकर सबको गले लगाएंगे।

अमेरिकी स्वर्ण पदक विजेता तैराक केटी लेडेकी ने वायरस संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहना था। ऑस्ट्रेलिया की लानी पैलेस्टर संक्रमित पाए जाने पर एक स्पर्धा से हट गईं, लेकिन बाद में 4x200 मीटर रिले में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियाई तैराक जैक स्टबल्टी कुक ने 200 मीटर बैकस्ट्रोक का रजत पदक जीतने के बाद कहा कि वह कोविड से जूझ रहे थे। ऐसे कई खिलाड़ी, जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी स्पर्धा में शामिल हुए। नीदरलैंड के हॉकी खिलाड़ी जॉरिट क्रून ने कहा कि वे खिलाड़ियों के बीमार होने की वजह से पदक जीतने का एक फीसदी मौका भी नहीं गंवाना चाहते। हॉकी का फाइनल खेलने वाली नीदरलैंड की टीमों के खिलाड़ियों का कहना है कि बस कुछ दिन की बात है। पदक जीतकर सबको गले लगाएंगे।

-साथ में तलया मिंसवर्ग और जेंगी ब्रेटास ©The New York Times 2024

आंकड़े

मातृभाषा

आंकड़ों के अनुसार, शहरी भारत के 57 फीसदी इंटरनेट उपयोगकर्ता अपनी मातृभाषा में इंटरनेट पर पढ़ना पसंद करते हैं।

43 फीसदी उपयोगकर्ता अंग्रेजी में सामग्री देखते हैं। स्रोत : IAMAI-Kantar

आज नागपंचमी है। परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए जनमेजय जब सर्पों को समाप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब आस्तिक ऋषि ने नागों की रक्षा की।

आस्तिक ऋषि ने की तक्षक की रक्षा

आस्तिक ऋषि जरत्कारु और मनसा के पुत्र थे। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए वह जीवों की रक्षा करते थे। तक्षक नाग के डसने की वजह से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय ने सर्पसत्र करके सभी सर्पों को नष्ट करने के लिए यज्ञ किया। अंत में तक्षक नाग की बारी आई। यह बात जरत्कारु को पता चली, तो उन्होंने आस्तिक को तक्षक की रक्षा करने के लिए भेजा।

आस्तिक ऋषि जनमेजय के यज्ञ मंडप में पहुंचे और अपनी मधुर वाणी से उनको मोह लिया। इधर, तक्षक भागकर इंद्र की शरण में पहुंचा और उनके सिंहासन से लिपट गया। तक्षक नहीं आया, तो जनमेजय ने 'इंद्राय तक्षकाय स्वाहा' कहना आरंभ कर दिया। इंद्र ने तक्षक को छोड़ दिया। उसी समय जनमेजय ने आस्तिक ऋषि से पूछा कि आपको क्या चाहिए, कृपा कर मांगें। इतना कहते ही आस्तिक ऋषि ने राजा से अनुरोध किया कि सर्पसत्र रोक दीजिए। वचनबद्ध होने के कारण जनमेजय ने खिन्न मन से आस्तिक की बात मानकर तक्षक को मंत्रप्रभाव से मुक्ति दी और यज्ञ बंद करा दिया। सर्पों ने प्रसन्न होकर आस्तिक ऋषि को वचन दिया कि जो भी व्यक्ति तुम्हारा आख्यान श्रद्धासहित पढ़ेगा, उसे हम कष्ट नहीं देंगे। बताया जाता है कि जिस दिन सर्पसत्र बंद हुआ था उस दिन श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उसी दिन से नागपंचमी मनाई जाती है।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 01 मई, 1957

अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद हो व विदेशी मूर्तियां हटें : लोहिया

अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बंद हो
विदेशियों की मूर्तियां हटें
डाक्टर लोहिया की ऐतिहासिक स्थापित करने की रायें

समाजवादी नेता डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा कि यदि सरकार सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दे और विदेशी लोगों की मूर्तियां हटाए, तो वह अपनी पार्टी से कहेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दे।

तैरता विकास, टेरता विनाश

हर आपदा का एक जैव-पारिस्थितिक पहलू होता है, जो कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण बहुतों को नुकसान पहुंचा जाता है।

संदीप जोशी — **पर्यावरण**

वायनाड और फिर कुल्लू-मनाली में जो आपदा बरसी, उसने 'विकास या विनाश' का मुद्दा फिर छेड़ दिया है। कोई भी आपदा अचानक, अकेले नहीं आती है। उससे पहले समाज और सत्ता में भी अच्छे विचार और सच्चे काम की कमी आती है। आपदा प्राकृतिक हो या मानवीय-हर आपदा का एक इकोलॉजिकल या जीव पारिस्थितिकी-तंत्र होता है, जो कुछ लोगों के निजी स्वार्थ के कारण बहुतों को नुकसान पहुंचा जाता है।

इसलिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जो भी जलवायु संबंधी आपदा घट रही है, उनके पीछे मानवीय स्वार्थ जिम्मेदार होता है। प्रकृति तो सदा परिवर्तनशील ही रही है, मगर आपदाग्रस्त नहीं। आखिर हर मानसून में बढ़ती जा रही इन भयावह त्रासदियों से हम कोई सीख क्यों नहीं लेते।

आज का विकास मॉडल प्रकृति के विनाश पर आधारित है। महंगाई और बेरोजगारी के बीच आलीशान इमारतें, सुपर हाईवे, पर्यटन कॉरिडोर व छह-लेन चौड़ी सड़कें उनसे जरूरी कैसे हो सकती हैं? विकास का जो मॉडल पिछले कुछ दशकों से देश में चलाया जा रहा है, उसे समाज और सत्ता के पैमाने पर देखना होगा। समाज के मन में यह घर कर गया है कि असल विकास तो विदेश का ही है और हमें देश में विदेश जैसा विकास चाहिए। यानी भारत को भौतिक तौर पर अमेरिका या इंग्लैंड ही बनाना है।

यह वैसा ही है, जैसा 1909 में महात्मा गांधी ने *हिंद स्वराज्य* में दर्शाने की कोशिश की थी। यानी हमें बाघ का स्वभाव (निरंकुशता) तो चाहिए, लेकिन बाघ (अंग्रेज) नहीं चाहिए। मगर बाघ का स्वभाव तो बाघ के साथ ही आएगा। प्रकृति में सभी की जरूरत ने लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन एक की भी लालसा के सामने वह कम ही रहने वाला है।

सिर्फ मुनाफे के लिए ही उद्योगपति विकास मॉडल के हिस्सेदार बनते हैं। इसलिए सड़कें बनानी हों या इमारतें, या कोई अन्य उद्योग लगाने हों, उस जमीन पर जीने-बसने वालों को अनावश्यक मान लिया जाता है। वायनाड, कुल्लू-मनाली या अन्य पहाड़ी इलाकों में सत्ता व उद्योगपतियों की सांठगांठ व सिर्फ मुनाफे का ही विकास दर्शाया। विकास के नाम पर पेड़ तो खूब काटे जाते हैं, मगर उतने पेड़ लगाए नहीं जाते। बादल फटने या तेज बारिश होने से भुरभुरी मिट्टी भूस्खलन ही लाती है। या नदी का जल बिना ठहरे तेजी से बहता है, तो रास्ते से सब कुछ बहा ले जाता है। नतीजतन आपदा आती है। समाज को विकास के लिए विवेक से काम लेना होगा।

ऐसी ही सांठगांठ दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर हादसे में भी दिखी। रिहायशी इलाकों में कोचिंग सेंटर चलाने की मंशा भी मुनाफे की ही रही है। बस उनमें पढ़ने वाले प्रतिभाशाली बच्चे दूसरे राज्यों से आए थे। वर्ष 1935-36 में गांधी जी ने तय किया कि देश के बीचों-बीच सेवा कार्य करने-सीखने का गांव बने। सेवाग्राम आश्रम उद्योगपति जमनालाल बजाज को बनाना था। गांधी जी ने बजाज से शर्त रखी कि आश्रम बनाने के लिए जो भी जरूरत होगी, वह उसके सिर्फ पांच किलोमीटर के दायरे से ही ली जाए। इसके उन्होंने तीन कारण बताए-आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और समरसता पैदा होगी। सभ्य समाज में सबका विकास ऐसी ही समरस अर्थव्यवस्था से होना चाहिए।

वायनाड, कुल्लू-मनाली और पहाड़ों में रहने-बसने वालों के लिए विकास का जो मॉडल अपनाया गया, उसमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जलवायु प्रदूषण होता है। विकास के नाम पर सात प्रतिशत जंगल काट दिए गए हैं। पर्यटकों के लिए पेड़-पहाड़ काट कर सड़कें बनाना वहां रहने-बसने वालों के लिए रोजगार का बहाना भर है। ऐसे ही रोजगार का विकास कभी दिल्ली आकर कुसुमपुर पहाड़ी पर या मुंबई के धारावी के स्तमों में बसे लोगों ने भी देखा था। आज वे न घर के हैं, न घाट के।

दिल्ली के जमनापार में एक उच्च मध्यवर्गीय कालोनी निर्माण विहार है। उसमें कभी बारिश के पानी को सहेजने के लिए अलग से खुली नालियां बनाई गई थीं। फिर विकास के नाम पर उन नालियों को ढक दिया गया, अब उन नालियों पर कारें खड़ी होती हैं। ढक देने से नालियों की सफाई नहीं होती और जल निकासी भी अवरुद्ध हो गई है। नतीजतन हर बारिश में कालोनी बाढ़ ग्रस्त होती है।

जन और जनसेवक अगर ईमानदारी से स्थानीय विकास पर जोर देते, देश कब का विकसित राष्ट्र बन जाता। समाज को ही एकजुट होकर संपोषणीय विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) के लिए आगे आना होगा, क्योंकि पारिस्थितिकी की समझ तो वहां जीने-बसने वालों से ही बनती है। असली विकास प्रकृति की सुरक्षा एवं संरक्षण से ही हो सकता है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 150

लक्ष्य पर नजर

गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 50वीं बैठक के नतीजे से किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। इसका अंदाजा पहले से था कि एमपीसी की बैठक में नीतिगत दरें यथावत रहेंगी और केंद्रीय बैंक के नजरिये में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा हुआ भी और आरबीआई ने रीपो दर 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी। एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति के अनुमानों में भी कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वृद्धि दर भी 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एमपीसी को लगता है कि समग्र मुद्रास्फीति (हेडलाइन इन्फ्लेशन) चालू वित्त वर्ष में औसतन 4.5 प्रतिशत के स्तर पर रह सकती है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में समग्र मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है।

यद्यपि, मौद्रिक नीति से संबंधित घोषणाओं में अधिकांश बातें अनुमानों के अनुरूप ही रहीं परंतु मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने के तरीके, मौद्रिक नीति संचालन एवं वित्तीय स्थिरता का खास तौर पर जिक्र किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन तीनों विषयों से जुड़ी मौलिक बातों का उल्लेख किया। नवीनतम आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 'भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करते समय खाद्य वस्तुओं को बाहर रखना चाहिए, अर्थात इस पर विचार नहीं करना चाहिए'। इसके पीछे मुख्य तर्क यह दिया गया कि खाद्य मुद्रास्फीति प्रायः मांग पर निर्भर नहीं करती है और आपूर्ति मोर्चे पर होने वाली हलचल इसे अधिक प्रभावित करती है। समीक्षा में कहा गया कि मांग में वृद्धि से मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से अल्प अवधि के नीतिगत उपायों से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। इस सप्ताह के शुरू में इस समाचार पत्र ने तर्क दिया था कि खाद्य मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने सभी बातों पर स्थिति स्पष्ट कर दिया है। इससे किसी भी तरह के संदेह के समाधान में मदद मिलनी चाहिए। इनमें कुछ व्यापक बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है।

समग्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर का लक्ष्य तय करना आरबीआई का प्रमुख ध्येय है। इस सूचकांक में खाद्य मुद्रास्फीति का भारांश लगभग 46 प्रतिशत है, इसलिए इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उपभोक्ता मुद्रास्फीति को अन्य बातों की तुलना में खाद्य कीमतों के संदर्भ में अधिक समझते हैं। ध्यान देने योग्य है कि मई और जून में समग्र मुद्रास्फीति में खाद्य महंगाई की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत से अधिक रही। खाद्य मुद्रास्फीति घरेलू बजट को भी प्रभावित करती है, जिसका भविष्य में वास्तविक मुद्रास्फीति की दशा-दिशा पर असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंता बढ़ गई है। खाद्य मुद्रास्फीति लगातार ऊंचे स्तर पर रहने से परिवारों का बजट बिगड़ सकता है और यह प्रमुख मुद्रास्फीति दर को भी प्रभावित कर सकता है। परिवारों में व्यवहार के स्तर पर बदलाव से मुद्रास्फीति समस्या का कारण बन सकती है और इससे आर्थिक लागत भी बढ़ जाएगी। एमपीसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को अधिक तवज्जो भले न दे परंतु, इनमें निरंतर बढ़ोतरी नजरअंदाज नहीं की जा सकती।

वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के संदर्भ में दास ने कहा कि खुदरा निवेशकों के लिए निवेश के वैकल्पिक साधन अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं और बैंकों के लिए जमा हासिल करना आसान नहीं रह गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बैंक ऋण आवंटन बढ़ाने के लिए अन्य स्रोतों से रकम जुटा रहे हैं परंतु यह व्यवहार संरचनात्मक तरलता से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि पिछले साल हुए एहतियाती उपायों के बाद भी व्यक्तिगत ऋण खंड में कुछ खास मामलों में अधिक रकम बांटी जा रही है। हालांकि, वित्तीय या बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता के लिए तत्काल कहीं से खतरा नजर नहीं आ रहा है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पूंजी की कमी नहीं है, परंतु केंद्रीय बैंक ने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्हें संकेत मानते हुए किसी संभावित खतरे को समय रहते दूर करने में कोई हर्ज नहीं है। पिछले कुछ दिनों में वैश्विक वित्तीय बाजार में मची उथल-पुथल पर आरबीआई ने अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है, जो एक अच्छी रणनीति है। बाहरी मोर्चे पर मजबूत स्थिति और आर्थिक वृद्धि लगातार जारी रहने की उम्मीदों के बीच एमपीसी अपने मकसद से नहीं भटकी है और मुद्रास्फीति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित रखा है।

अजय मोहंती

जीएसटी: रियल्टी व भूमि तक विस्तार पर हो जोर

जमीन एवं रियल एस्टेट को जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत लाने से फैक्टर मार्केट में सुधारों को गति मिलेगी, जिससे भारत की आर्थिक तरक्की को मजबूती मिलेगी। बता रहे हैं वी एस कृष्णन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के अपने बजट भाषण में उल्लेख किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) वास्तव में एक बड़ा सुधार रहा है और यह महत्त्वपूर्ण बदलाव का जरिया साबित हुआ है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी का दायरा बढ़ाने एवं दरें सरल तथा उचित बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। दरें उचित या तर्कसंगत बनाने पर समिति के सुझाव औसत जीएसटी भुगतान दर को मौजूदा 12.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 14.8 प्रतिशत राजस्व तटस्थ दर (जीएसटी प्रभावी होने से पहले प्रचलित दर) तक पहुंचाने में मददगार होंगे।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु जीएसटी का दायरा बढ़ाना है। कुछ अर्थशास्त्री पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के अंतर्गत लाने का सुझाव लगातार दे रहे हैं। मेरे विचार में इस कार्य के लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि राजकोषीय संप्रभुता बनाए रखने, खासकर आपात स्थितियों से निपटने के लिए कुछ राज्य पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने पर हामी नहीं भर पा रहे हैं।

हालांकि एक ऐसा बिंदु है जिस पर बहुत चर्चा नहीं हुई है परंतु इसका असर जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व से अन्यत्र भी दिख सकता है। वह बिंदु है जमीन एवं रियल एस्टेट को जीएसटी के अंतर्गत लाना। इससे भूमि बाजार में होने वाले सौदों में पारदर्शिता आएगी, आयकर राजस्व में इजाफा होगा और आवासीय बाजार में अधिक विदेशी निवेश भी आएगा, जिससे रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। इस पहल के लिए स्पष्ट रूप से राज्यों के बीच आम सहमति होनी चाहिए और जीएसटी लागू किए जाने से पहले वास्तव में इस पर काफी माथापच्ची हुई थी। सबसे पहले केंद्र को कानूनी पहलू स्पष्ट करते हुए राज्यों में बैठा डर दूर करने की जरूरत है। जमीन एवं रियल एस्टेट पर जीएसटी लागू करने के बाद भी राज्यों को स्टांप शुल्क या स्थानीय निकायों को संपत्ति कर लगाने से नहीं रोका गया है। जमीन एवं रियल एस्टेट पर जीएसटी लागू करने की राह में कोई बाधा नहीं है। साथ ही राज्य भी स्टांप शुल्क लगाना जारी रख सकते हैं क्योंकि दोनों मामलों में कराधान अलग-अलग हैं। उच्चतम न्यायालय भी यह सिद्धांत मानता है और उसने इस क्षेत्र पर एक से अधिक कर लगाए जाने को सही करार दिया है। भारतीय संविधान में जमीन एवं अचल संपत्ति को वस्तु की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। सिंगापुर में जमीन के इस्तेमाल के अधिकार की बिक्री 'वस्तु' मानी गई है मगर भारत में जमीन इस्तेमाल करने के अधिकार को निश्चित तौर पर 'डीम्ड सर्विस' (सेवा मान ली गई है) मान सकते हैं।

जीएसटी को कारगर बनाने के लिए इसके दायरे में जमीन से लेकर रहने की अस्थायी जगह (लॉज) सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला (भूमि के विकास से लेकर इस पर निर्माण और तैयार जायदाद की पहली बिक्री) शामिल की जानी चाहिए। कानूनी रूप से यह स्वीकार्य है। जमीन की बिक्री को जमीन के अधिकार की बिक्री मानते हुए सेवा कहा जा सकता है और उस पर कर लगाया जा सकता है।

इस कदम से अवैध आय कमाने पर रोक लगेगी और भूमि विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे गैर-कृषि भूमि बेकार नहीं पड़ी रहेगी और उनका वाजिब इस्तेमाल भी हो पाएगा। जीएसटी लगाने से निर्माण सेवाओं और इस्तेमाल के लिए तैयार (रेडीमेड) जायदाद के बीच मौजूदा अंतर समाप्त हो जाएगा। अभी निर्माण सेवाओं पर कर लग रहा है किंतु इस्तेमाल के लिए तैयार जायदाद को मुक्त रखा गया है। जमीन या जायदाद खरीदने वाले को जीएसटी के झंझट से मुक्त रखने के लिए इसका भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत सेवा प्रदाता (डेवलपर एवं बिल्डर) से कराया जा सकता है।

जीएसटी राजस्व में बहुत अधिक इजाफा नहीं होगा क्योंकि इसमें मिलने वाला कर निर्माण उद्योग द्वारा इस्तेमाल होने वाली लोहा-इस्पात, सीमेंट, फिक्सचर जैसी निर्माण सामग्री पर लगाए गए करों पर दिए जाने वाले इनपुट ड्यूटी क्रेडिट के रूप में चला जाएगा। राजस्व में बढ़ोतरी आयकर के मोर्चे पर होगी मगर इसके लिए सौदे के वास्तविक मूल्य की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। सस्ते आवास (250 वर्ग फुट कारपेट एरिया से कम क्षेत्रफल वाले मकान) शुल्क मुक्त रखे जा सकते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकारी आवासीय कार्यक्रम भी जीएसटी की जद से बाहर रखे जा सकते हैं।

जीएसटी प्रणाली में जमीन एवं रियल एस्टेट शामिल करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची 3 से इसे हटाना होगा। सीजीएसटी अधिनियम में जमीन एवं इमारतों की बिक्री को न तो वस्तु आपूर्ति माना गया है और न ही सेवाओं की आपूर्ति (वास्तव में ये सेवाओं की आपूर्ति मानी जानी चाहिए)। इनपुट टैक्स क्रेडिट नियमों में भी संशोधन की जरूरत होगी क्योंकि इसमें फिलहाल जमीन एवं इमारत में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर शुल्क क्रेडिट की अनुमति नहीं है।

यह नीतिगत कदम आवास क्षेत्र के लिए बड़े सकारात्मक बदलाव लाने वाला होगा। यह कदम श्रम बल की अधिक जरूरत वाले इस खंड में बड़े पैमाने पर निवेश लाएगा। यह उपाय फैक्टर मार्केट (आर्थिक गतिविधि में योगदान देने वाले सभी कारक) खासकर जमीन एवं श्रम में सुधारों पर मौजूदा सरकार की सोच से भी मेल खाएगा। जीएसटी में जमीन एवं रियल एस्टेट शामिल करने से रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम या रेरा के लाभ और बढ़ जाएंगे।

सरकार को विमान ईंधन (एटीएफ) एवं प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। एटीएफ यदि जीएसटी में आ गया तो विमानन क्षेत्र को कच्चे माल पर टैक्स क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा। इसी तरह प्राकृतिक गैस एक मध्यवर्ती कच्ची सामग्री है, जिसका इस्तेमाल उर्वरक जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भी होता है। अक्षय ऊर्जा खंड को शामिल करना एक और बड़ा कदम हो सकता है। पूरे बिजली क्षेत्र को एक साथ जीएसटी में लाने के बजाय पहले चरण में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर एवं पवन ऊर्जा) के साथ पहल की जा सकती है। यह क्षेत्र अधिक पूंजी निवेश, कम लागत एवं कम समय में परियोजनाएं पूरी करने के लिए जाना जाता है। इसे जीएसटी में लाए जाने से पूंजीगत वस्तुओं से जुड़े करों पर लाभ लेने में मदद मिलेगी।

जीएसटी के दायरे में विस्तार के सुझाव (खासकर जमीन एवं रियल एस्टेट के संदर्भ में) से फैक्टर मार्केट सुधारों को गति मिलेगी, जो अगले दो दशकों में रोजगार युक्त आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी होगा।

(लेखक सीबीआईसी के सदस्य रह चुके हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

पी2पी उद्योग पर आरबीआई की बढ़ती नजर

भारत में ऋणदाताओं को ऋण लेने वालों से ऑनलाइन माध्यम से मिलाने वाले पीयर टू पीयर (पी2पी) ऋण क्षेत्र के हालात को समझने के लिए एक घटना ही काफी है। मई में 'ए' नाम के व्यक्ति ने पी2पी प्लेटफॉर्म पर उधार देने के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। यहां किसी निवेशक या बैंक का नाम नहीं बताया जा रहा है। ए ने 3 मई को रकम डाली और पी2पी प्लेटफॉर्म पर 9 मई को पैसा दिखने लगा। उन्होंने निवेश के लिए 'मैनुअल' विकल्प चुना। इसके अलावा 'ऑटो' निवेश का भी विकल्प होता है। मैनुअल निवेश प्रक्रिया में निवेशक खुद ही कर्ज लेने वालों को चुनते हैं और प्लेटफॉर्म निवेशकों के निर्देश पर काम करते हैं। ऑटो निवेश वाले माध्यम में प्लेटफॉर्म क्रेडिट मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर यानी, भावी कर्जदार के क्रेडिट स्कोर और नकदी आदि की जांच करते हैं (मसलन कर्ज लेने वाला व्यक्ति वेतनभोगी है या नहीं)।

कर्ज लेने वालों को चुनने के इरादे से ए ने 16 मई को प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर गए। उन्होंने देखा कि निवेश के लिए पैसा उपलब्ध नहीं था क्योंकि 10,000 रुपये पहले ही 165 ऋणों के लिए दिए जा चुके हैं और औसत ऋण राशि 60.60 रुपये थी। यह ठीक भी था क्योंकि इस तरह जोखिम कम रहता है। ए के मामले जो बात ठीक नहीं थी वह यह थी कि उधार लेने वालों में 11.5 प्रतिशत लोगों यानी 19 लोगों ने पहले ही उनसे लिए गए ऋणों की किस्त का भुगतान कम से कम 30 दिन से नहीं किया था। इसे भुगतान में चूक या डिफॉल्ट का पहला चरण कह सकते हैं। अगर कोई कर्जदार 90 दिनों तक कर्ज बिल्कुल नहीं चुकाता है तब वह कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाता है। सवाल यह है कि अगर कोई 9 मई को निवेश करता है तब पैसा अप्रैल या उससे पहले उधार लेने वालों को कैसे दिया जा सकता है, जिनमें से कुछ पहले से ही ऋण भुगतान में चूक कर चुके हैं?

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

जून के मध्य तक ए के कर्जदारों संख्या घटकर 136 रह गई, लेकिन 30 दिन तक कोई भी भुगतान नहीं होने वाले ऋणों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। इसके अलावा सात एनपीए थे। जुलाई के मध्य तक कर्जदार घटकर 85 ही रह गए। इस बार 24 ऋण या दिए गए एक-चौथाई से अधिक ऋण पर 30 दिनों से भुगतान नहीं हुआ था और छह ऋण एनपीए थे।

ए को हर महीने ब्याज तो मिल रहा था (उन्हें 8.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का वादा किया गया था) लेकिन सवाल यह है कि उनके पैसे प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही लोगों को ऋण के तौर पर कैसे मिल सकते थे? एक ऋणदाता के तौर पर भी ए के खाते में एनपीए कैसे हो सकते हैं, जब उन्होंने कर्ज देना ही जून में शुरू किया था? इसका जवाब यह है कि जो कर्ज पहले से फंसे हैं, उनमें नए ऋणदाताओं की रकम लगा दी जाती है।

मुझे भी यह जानना है कि आखिर ए ने 8.5 फीसदी ब्याज की कमाई करने के लिए पी2पी बाजार में प्रवेश क्यों किया, जब कुछ बैंक सावधि जमाओं पर इतना ही या थोड़ा अधिक ब्याज दे रहे हैं? ऐसा लगता है कि पी2पी प्लेटफॉर्म के लिए आकर्षण का केंद्र तुरंत मिलने वाली नकदी हो सकती है। वैसे 8.5 प्रतिशत ब्याज कमाना बुरा नहीं है क्योंकि म्युचुअल फंड लगभग 6.5 प्रतिशत ही दे रहे हैं।

यह स्पष्ट है कि कुछ पी2पी प्लेटफॉर्म जमा लेने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तरह बरताव कर रहे हैं। वे सामूहिक निवेश योजनाएं भी चला रहे हैं जहां विभिन्न ऋणदाताओं से मिली रकम का पूल बनाया जाता है और कई कर्ज लेने वालों को ऋण दे दिए जाते हैं। यह पहली बीमारी है।

अब दूसरी बीमारी की ओर नजर डालते हैं। कुछ पी2पी प्लेटफॉर्म जोखिम से बचने के लिए तथाकथित मार्जिन दे रहे हैं। आखिर यह क्या है? जब निवेशक 8.5 प्रतिशत कमा रहे होते हैं तब हो सकता है कि कुछ कर्जदार 22 फीसदी तक ब्याज चुका रहे हों। दोनों के बीच का अंतर 13.5 फीसदी है जो सुरक्षा का मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि जब तक कुल ऋणों का 13.5 प्रतिशत से अधिक एनपीए नहीं होता तब तक निवेशक को पूंजी का नुकसान नहीं होगा।

क्या आरबीआई के मानदंड क्रेडिट जोखिम कम करने के लिए एस्क्रो अकाउंट (एक विशेष खाता होता है जिसमें कुछ शर्तें पूरी होने तक पैसे या संपत्ति रखी जाती है) में सुरक्षा मार्जिन जैसी रकम रखने की अनुमति देता है? क्या जोखिम कर्ज देने वालों का नहीं उठाना चाहिए? क्या ये प्लेटफॉर्म महज जोड़ी मिलाने वाले (फीस लेकर) की भूमिका में नहीं हैं? सुरक्षा का मार्जिन कुछ नहीं बल्कि ऋण की गारंटी और ऋण प्रणाली है। नियामक द्वारा परिभाषित एनबीएफसी-पी2पी इकाई की गतिविधियों का दायरा कुछ इस तरह है:

- पीयर-टू-पीयर ऋणदाता के तौर पर शामिल प्रतिभागियों के लिए एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस या प्लेटफॉर्म वाले मध्यस्थ की भूमिका में रहें
- आरबीआई अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 451 (बीबी) के तहत या उसके तहत परिभाषित जमा को बढ़ावा न दें
- खुद कर्ज न दें
- किसी ऋण गारंटी की व्यवस्था न करें
- उधार देने के लिए ऋणदाताओं से मिली राशि या ऋणों के भुगतान के लिए कर्जदारों से मिली रकम को अपनी बैलेंसशीट में शामिल न करें...

तीसरी बीमारी परिसंपत्ति-देनदारी का बेमेल है, जिसे कुछ पी2पी ऋणदाता अपने खाते में ले रहे हैं। निवेश के लिए तीन महीने तक की अनुमति है लेकिन ऋण एक साल तक के लिए दिए जाते हैं।

हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), मुंबई में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव ने कहा, 'एनबीएफसी-पी2पी का कारोबारी संचालन नियामकीय दिशानिर्देश के अनुरूप नहीं लगता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि लाइसेंस से जुड़ी शर्तों और नियामकीय दिशानिर्देश में कोई भी उल्लंघन स्वीकार्य नहीं है।'

नियामक ने हाल ही कुछ पी2पी प्लेटफॉर्म को उनके कुछ कदमों की वजह से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। अब देखना है कि वे अपना बचाव कैसे करते हैं और नियामक इस पर प्रतिक्रिया कैसे देता है।

आपका पक्ष

अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों

नई स्वास्थ्य नीति के माध्यम से सभी नागरिकों को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। लेकिन देश में नीतियां तो बहुत बनती हैं, लेकिन उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का ठीक से क्रियान्वयन हो, ताकि गांव के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था में व्याप्त खामी के मुख्य कारक, शहरी और ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में अंतर तथा सार्वजनिक चिकित्सा सेवाओं के लिए आवंटन की कमी है। इलाज और सेहत की आम देखरेख, अब अधिक से अधिक निजी क्षेत्र के दायरे में चले गए हैं। नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सरकारी इलाज तंत्र को बेहतर स्थान दिलाने का प्रावधान व संकल्प प्रदर्शित किया है। जब तक सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में बढ़ोतरी नहीं करती, नीति में वर्णित बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। केंद्र ने अगर राज्यों से मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल में केंद्रीय स्थान देने की ठोस योजना नहीं बनाई, तो सही नीतिगत दिशा के बावजूद जमीनी हालात जहां के तहां बने रहेंगे।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरुवार को 300 बिस्तर वाले 'सुपर स्पेशलिटी' अस्पताल का उद्घाटन किया।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ में संशोधन

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और आयकर संशोधनों से संबंधित समाचार केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था के विषय में सुधारवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की गणना में इंडेक्सेशन को लेकर वित्त मंत्रालय में निवेदन किए गए जिनमें इंडेक्सेशन के प्रावधान को वापस लाने के लिए यत्न किए गए और वित्त मंत्री ने उनको स्वीकार किया जो स्वागत योग्य है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कोई राजस्व संग्रहण का स्रोत नहीं है और इनका प्रयोजन करदाता द्वारा अपनी कैपिटल गेन देयता के योग्य अपनी संपत्ति को आवश्यकता अनुसार मोनेटाइजेशन करने और अन्य निवेश करने का अवसर देता है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के उद्देश्य से अचल संपत्ति की होल्डिंग को तीन वर्ष से दो वर्ष करना बहुत प्रशंसनीय है और इसका भी दूरगामी लाभ होगा। सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य की इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास की परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़े। इसका सरलतम मार्ग भी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की संगणना में उपलब्ध हो सकता है। दीर्घकालिक और अल्पकालिक पूंजी गत लाभ से औद्योगिक और व्यापारिक संपत्ति में निवेश की अनुमति मिले जो अभी तक ग्रह संपत्ति के लिए ही उपलब्ध है। साथ ही कैपिटल गेन टैक्स से मुक्ति के लिए धारा 54 ईसी के अंतर्गत निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। बहुत से करदाताओं को अपनी संपत्ति बेचने के बाद किसी और संपत्ति को खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे करदाताओं के लिए कोई अच्छे ब्याज के दीर्घकालिक इन्फ्रास्ट्रक्चर करमुक्त बॉन्ड भी जारी किए जा सकते हैं जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश बढ़े।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को न्यूजीलैंड के वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुर्मू तीन देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को न्यूजीलैंड पहुंचीं। मुर्मू ने वेलिंगटन में फुकियाहु राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को भी पुष्पांजलि अर्पित की। फुकियाहु राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन 18 अप्रैल, 2015 को किया गया था और इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के 100 वर्ष पूरे होने पर किया गया था।

दैनिक जागरण

अनुशासन के अभाव में जीवन दिशाहीन हो जाता है

सरकार का सही कदम

मोदी सरकार ने बहुचर्चित वक्फ अधिनियम में संशोधन वाला विधेयक लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की मांग पर ध्यान देते हुए उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का जो फैसला लिया, वह इस दृष्टि से सही कदम है, क्योंकि इस समिति में उस पर विस्तार से और संभवतः दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार हो सकेगा। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि विपक्ष के पास यह बहाना नहीं रह जाएगा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण विधेयक बिना बहस आनन-फानन पारित करा लिया और उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। ध्यान रहे कि मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में अनेक विधेयकों के संसद से पारित होने और उनके कानून में परिवर्तित हो जाने के बाद विपक्ष ने यह माहौल बनाया कि उन पर संसद में चर्चा नहीं होने दी गई। ऐसे कुछ कानूनों को लेकर जनता को बरगलाने का भी काम किया गया। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और फिर कृषि संबंधी तीन कानूनों को लेकर विपक्ष ने अपने सर्कीर्ण राजनीतिक हितों के लिए किस तरह जनता को गुमराह किया। देखना है कि शीघ्र गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति वक्फ संशोधन अधिनियम पर किस तरह विचार करती है और वह कोई आम सहमति कायम कर पाती है या नहीं? चूंकि ऐसी समितियों की बैठकें सार्वजनिक रूप से नहीं होतीं, इसलिए उनमें विचार-विमर्श कहीं अधिक धीर-गंभीर तरीके से होता है। प्रश्न यह है कि ऐसा ही विचार-विमर्श लोकसभा और राज्यसभा में क्यों नहीं हो सकता? क्या इसलिए, क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही का टीवी पर सीधा प्रसारण होता है और आमतौर पर सांसद किसी विषय पर कोई सार्थक सुझाव देने के बजाय अपने क्षेत्र की जनता और समर्थकों को कोई राजनीतिक संदेश देना ज्यादा जरूरी समझते हैं?

माना यह गया था कि संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा, लेकिन अभी तक का अनुभव यही अधिक बताता है कि जबसे विधानमंडलों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने लगा है, तबसे विधायी सदनों में सार्थक चर्चा के स्थान पर हंगामा अधिक होने लगा है। इसकी सराहना नहीं की जा सकती कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लोकसभा में पेश होते ही विपक्षी दलों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। उसकी ओर से यह घिसा-पिटा तर्क भी दिया गया कि सरकार मुस्लिम समाज के हितों की अनदेखी कर रही है। ऐसे तर्क इसलिए हास्यास्पद हैं, क्योंकि सच यह है कि वक्फ बोर्ड अरबों रुपये की संपत्तियों के स्वामी होने के बावजूद मुस्लिम समाज की भलाई के लिए कुछ ठोस नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद भी विपक्ष सुधार की एक सही पहल पर मुस्लिम समाज के मन में भय का भूत खड़ा करना चाहता है। यह वोट बैंक की सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं।

नशे के विरुद्ध अभियान

पंजाब के लिए नासूर बन चुके नशे के विरुद्ध पंजाब पुलिस लगातार अभियान चला रही है। यह अच्छी बात है कि उच्चाधिकारी स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश भर में बड़े स्तर पर नशे के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें बड़े पुलिस अधिकारी स्वयं भी शामिल हुए। पुलिस की विभिन्न टीमों ने अभियान के दौरान 61 एफआइआर दर्ज करने के साथ ही 82 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि नशीले पदार्थों की कोई बड़ी बरामदगी नहीं हो सकी। पुलिस के व्यापक प्रयासों की बाद भी यह चिंता का विषय है कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रुक रही है। प्रदेश के किसी न किसी हिस्से से आए दिन युवाओं की ओर से नशे के सेवन की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। लगभग प्रतिदिन ही नशीले पदार्थों के सेवन से किसी न किसी की जान जा रही है। प्रदेश में न जाने कितने घर नशे के कारण उजड़ चुके हैं। यह अच्छी बात है कि पुलिस नशे को रोकने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, लेकिन इस बात की भी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है कि इतने प्रयासों के बाद भी आखिर हर गली-मुहल्ले, गांव-गली में नशीले पदार्थ कैसे सुलभ हैं। इस आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस विभाग के ही कुछ कर्मचारी तस्करों से मिले हुए हों अथवा इन्हें किसी प्रकार का सियासी संरक्षण मिल रहा हो। गहराई से जांच कर इसका पर्दाफाश करना चाहिए और विभाग में भी काली भेड़ों की सफाई के लिए अभियान चलाना चाहिए। चौतरफा प्रयासों से ही नशे के विरुद्ध अभियान सफल हो सकता है।

> पुलिस के व्यापक प्रयासों की बाद भी यह चिंता का विषय है कि प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं रुक रही है

समय की मांग है संसदीय मर्यादा का पालन

ओम बिरला

यदि सदन में व्यवधान नियमित घटना बन जाए तो इससे न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि हमारे संस्थानों की नकारात्मक छवि भी बनती है

आवश्यकता है कि सदस्य अध्यक्ष पीठ के निर्देशों का अनुसरण करें। आसन पर बैठने के पश्चात अध्यक्ष किसी दल विशेष या विचारधारा विशेष का नहीं होता, बल्कि संसदीय लोकतंत्र का निष्पक्ष प्रहरी होता है। संसदीय संस्थाओं की उच्च मर्यादा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सदस्य किसी भी परिस्थिति में अध्यक्ष के प्राधिकार पर प्रश्न न उठाएं और उसके निर्देशों की अवहेलना न करें।

विधानमंडल परिसर के अंदर उत्पन्न सभी मुद्दों पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है और विधायिका के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्य अध्यक्ष के आदेश का पालन करें। सदस्यों को अध्यक्ष को एक व्यक्ति के रूप में न देखते हुए एक संस्था के रूप में देखना चाहिए, जो संसद के विशेषाधिकारों एवं शक्तियों का प्रतीक है। सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि नागरिकों द्वारा संसद सदस्यों को आदर्श माना जाता है। इसलिए विधायिका के सदस्यों का आचरण गरिमापूर्ण, अनुशासित, अनुकरणीय और दोषरहित होना चाहिए। प्रत्येक जनप्रतिनिधि के लिए संविधान की भावना से संसद के सदनों में आचरण के उच्च मानक बनाए रखना अनिवार्य है।

(लेखक लोकसभा अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

विधायी निकायों को पर्यवेक्षण, विधि-निर्माण एवं वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस तथ्य के दृष्टिगत कि भारत में दशकों से एक कार्यशील और मजबूत संसदीय लोकतंत्र है, विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखना और महत्वपूर्ण हो गया है। यदि सदन में व्यवधान नियमित घटना बन जाए तो इससे न केवल करदाताओं के पैसे की भारी बर्बादी होती है, बल्कि हमारे संस्थानों की नकारात्मक छवि भी बनती है, जिसके चलते लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास घट सकता है। विधायिका में अनुशासन और शिष्टाचार का अभाव हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। देश में विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का शीर्ष निकाय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (एआइपीओसी) ने विधानमंडलों में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसने रचनात्मक विमर्श और संवाद के जरिये विधानमंडलों के समक्ष समस्याओं के समाधान निकाले हैं, जिनमें अनुशासन और मर्यादा का मुद्दा भी शामिल है।

एक शताब्दी से अधिक की अपनी यात्रा के दौरान इस सम्मेलन द्वारा विधानमंडलों में मर्यादा और गरिमा से जुड़े अनेक मुद्दों पर विमर्श हुआ है। नवंबर, 2001 में हुए सम्मेलन में 'संसद और राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार'' विषय पर गहन चर्चा हुई। उसमें इस विषय पर सर्वसम्मति से एक संकल्प और आचार संहिता स्वीकार की गई। एआइपीओसी के प्रयासों के फलस्वरूप एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया, जो 2015 से लोकसभा की स्थायी समिति बन गई है। इसकी सिफारिशों का सदस्यों के आचरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। संसदीय मर्यादा के अंतर्गत कुछ नियम, परिपाटियां और शिष्टाचार शामिल हैं, जिनका पालन सदस्यों को विधायी सदन में करना होता है। सार्थक विचार-विमर्श और निर्णय लेने हेतु अनुकूल परिवेश बनाने के लिए आवश्यक है। संसदीय शिष्टाचार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिन्हें लेकर सभी पक्षों की सहमति है, जैसे अध्यक्ष पीठ के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन, सदन में चर्चाधीन विषयों पर संगत भाषण, सदन में अनुशासित आचरण, अन्य सदस्यों के भाषण में व्यवधान न डालना, सदन के अंदर शोर न करना तथा सदन में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न उत्पन्न करना।

'सदस्य का आचरण' शब्द को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह निर्धारित करने की शक्ति सभा के पास होती है कि क्या किसी सदस्य ने अशोभनीय व्यवहार किया है या कोई ऐसा व्यवहार किया है, जो एक संसद सदस्य के लिए अनुचित है। सभा में सदस्यों के गरिमापूर्ण और मर्यादित आचरण को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में कई प्रविधान हैं। सदस्यों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिससे संसद और उसके सदस्यों की गरिमा बढ़े। सदस्यों का आचरण संसदीय परंपराओं या उन मानकों के विपरीत न हो, जिनकी संसद सदस्यों से अपेक्षा की जाती है। संसदीय विशेषाधिकार सदस्यों को बिना किसी भय या व्यवधान के सदन में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। संविधान प्रदत्त संसदीय विशेषाधिकार अमूल्य हैं, इसलिए सदस्यों को सदन में इनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए, ताकि सदन के समय का सार्थक उपयोग हो और सदन के माध्यम से लोकहित के अधिकतम कार्य प्रभावी रूप से किए जा सकें।

लोकसभा अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष और व्यवस्थित कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा चर्चा के दौरान सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। अध्यक्ष न केवल सभा की बैठकों का संचालन करता है, उस पर समुचित नियम, परिपाटियां, परंपराएं और एक स्वस्थ संसदीय संस्कृति विकसित करने की जिम्मेदारी भी होती है। उसके व्यापक उत्तरदायित्वों को देखते हुए लोकसभा द्वारा अध्यक्ष को नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखना अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके लिए उसे नियमों और परंपराओं के तहत पर्याप्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब कोई सदस्य अनुचित या अपमानजनक टिप्पणी करता है तो अध्यक्ष हस्तक्षेप कर सकता है और सदस्य से उस टिप्पणी को वापस लेने के लिए कह सकता है या वाद-विवाद के दौरान प्रयुक्त किए गए किन्हीं अपमानजनक या अभद्र शब्दों को हटाने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष अनुचित आचरण करने वाले किसी सदस्य को सदन से बाहर जाने का आदेश भी दे सकता है और यदि सदस्य अध्यक्षपीठ की अवहेलना करता है और सभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान उत्पन्न करके घोर अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो अध्यक्ष किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि सदस्य अध्यक्ष पीठ के

संकट में बांग्लादेशी हिंदुओं का अस्तित्व

ऊर्जा

ईश्वर से प्रेम

समय बहुत बहुमूल्य है। इसलिए न अपना समय व्यर्थ करें और न दूसरों का। जो समय के मूल्य से परिचित हैं, वे क्षण भर भी इसका दुरुपयोग नहीं करते। हमें परमात्मा ने दुर्लभ मानव जीवन प्रदान किया है, अगर मानव जीवन का मूल्य न समझे तो इसमें परमात्मा का क्या दोष? यह जीवन अभी है और कुछ ही क्षणों के पश्चात नहीं भी। कब कौन किस पल इस धरती से अलविदा हो जाएगा? कब किसका किस समय बुलावा आ जाए, कौन जानता है? चंद पलों का ही तो मानव जीवन है।

क्या परमात्मा ने मनुष्य को 84 लाख योनियों में इतनी सर्वश्रेष्ठ योनि सिर्फ खाना-पूर्ति के लिए प्रदान की है? परमात्मा ने मनुष्य को जीने के लिए निःशुल्क प्राणवायु, प्रकाश और जल प्रदान किए हैं। साफ है ऐसा जीवन परमात्मा ने सिर्फ प्रजनन, माया, मोह, लोभ, लालसा, लिप्सा, भोग-विलास, वासना, कामना, विषयासक्ति, संसारिकता एवं भौतिकता के लिए नहीं प्रदान किया है। वास्तव में मनुष्य योनि इस संसार में परमात्मा का दूजा रूप है, हमशक्ल है। परमात्मा की तरह सभी क्षमताएं मानव के अंदर कूट-कूटकर भरी हुई हैं। सिर्फ इसे पहचानने एवं विकसित करने की देर है। परमात्मा ने जो सृष्टि रची है, इस विश्वउद्यान रूपी बगीचे के कुशल माली की भूमिका के निर्वहन के लिए हमें नियुक्त किया है, ताकि यह विश्वउद्यान रूपी बगीचा सूखे नहीं, सदा हरियाली संपन्न रहे। हालांकि मनुष्य इस संसार में समय सांसारिक विषय-वस्तुओं से प्रेम करने में ही निरर्थक व्यतीत कर देता है। कुछ शाश्वत अर्जित नहीं कर पाता है।

आया था मनुष्य इस संसार में परमात्मा से प्रेम, प्रभु का काम करने के लिए, लेकिन जीवन का पूरा समय संसार,माया-मोह, विषय-वासना से प्रेम करने में व्यतीत करके अलविदा हो जाता है और दुर्लभ मानव जीवन को कलंकित कर देता है। ऐसी नासमझी मानव जीवन के लिए लाभप्रद नहीं, मुक्ति में बाधक और अति निंदा योग्य है।

मुकेश ऋषि

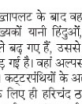

कृपाशंकर चौबे

बांग्लादेशी हिंदुओं के पास तीन ही रास्ते हैं- या तो आत्महत्या कर लें या मुस्लिम बन जाएं या फिर पलायन कर जाएं

खतरे में हैं बांग्लादेश के हिंदू। प्रेट्र

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद वहां जिस तरह अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं, बौद्धों आदि पर हमले बढ़ गए हैं, उससे उनकी सुरक्षा फिर से खतरे में पड़ गई है। वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नए नहीं हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से नमशूद्रों को बचाने के लिए ही हरिचंद ठाकुर ने 19वीं सदी के मध्य में फरीदपुर (तत्कालीन पूर्वी बंगाल) में मतुआ पंथ की स्थापना की थी। मतुआ यानी जो मानवतावादी मतवाले हैं। कट्टरपंथियों के अत्याचार से बचने के लिए गुरुचंद ठाकुर के पौत्र प्रमथ रंजन बिश्वास 1948 में बंगाल के बनगांव आ गए थे। उन्होंने बंगाल में मतुआ धर्म महासंघ की संगठित किया। मतुआ धर्म महासंघ बंगाल में अपने डेढ़ करोड़ अनुयायियों के साथ आज भी नमशूद्र शरणार्थियों के लिए संघर्षरत है। विभाजन के समय कट्टरपंथियों के अत्याचार रोकने के लिए ही जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान सरकार में शामिल हुए। जब पाकिस्तान में कानून एवं श्रम मंत्री बनने के बाद भी वह अत्याचार नहीं रोक पाए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नौ अक्टूबर, 1950 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को भेजे त्यागपत्र में मंडल ने लिखा था कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के जैसे हमले बढ़ते जा रहे हैं, उससे उनका मंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा था कि देश विभाजन के बाद 50 लाख हिंदू पलायन करने को विवश हुए हैं। हिंदुओं का पलायन उसके बाद भी थमा नहीं।

बांग्लादेशी साहित्यकार सलाम आजाद ने अपनी पुस्तक 'बांग्लादेश से क्यों भाग रहे हैं हिंदू' में लिखा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के अत्याचार से तंग आकर 1974 से 1991 के बीच रोज औसतन 476 लोग यानी हर साल एक लाख 73 हजार 375 हिंदू हमेशा के लिए बांग्लादेश छोड़ने को बाध्य हुए। यदि उनका पलायन नहीं हुआ होता तो आज बांग्लादेश में हिंदू नागरिकों की आबादी सवा तीन करोड़ होती। सांप्रदायिक उत्पीड़न, सांप्रदायिक हमले, नौकरियों में भेदभाव, दमनकारी शत्रु अर्पित संपत्ति कानून और देवोत्तर संपत्ति पर कब्जे ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को कहीं का नहीं छोड़ा है। सलाम आजाद ने लिखा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के पास तीन ही रास्ते हैं-या तो वे आत्महत्या कर लें या मतांतरण कर मुसलमान बन जाएं या पलायन कर जाएं। सलाम आजाद ने अपनी कृति 'शर्मनाक' में लिखा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के पिता के सामने बेटी के साथ और मां-बेटी को पास-पास रखकर दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्मियों की पाशविकता से सात साल की बच्ची से लेकर सात साल की वृद्ध तक को मुक्ति नहीं मिली। बांग्लादेश से हिंदुओं को नेस्तनाबूद कर वहां उग्र इस्लामी तथा तालिबानी राजसत्ता कायम करने के मकसद से हिंदुओं पर चौतरफा अत्याचार किया गया।

सलाम आजाद ने जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार का सवाल उठाया तो उन्होंने उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया। उन्हें देश से निर्वासित होना पड़ा। शेख हसीना की सरकार बनने पर ही वह अपने देश लौट सके। तसलीमा नसरीन तो शेख हसीना के शासनकाल में भी अपने देश नहीं लौट सकीं। तसलीमा का उपन्यास 'लज्जा' तीन दशक पहले प्रकाशित हुआ तो कट्टरपंथियों ने उनकी मौत का फतवा जारी कर दिया। तसलीमा आज भी अपने उस देश की कुशलता की कामना करती हैं, जो 1971 में बना। वर्ष 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का उदय पाकिस्तानी सेना के अकथ्य अत्याचार का परिणाम था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने यह साबित किया कि मजहब के आधार पर राष्ट्र-राज्य के निर्माण का सिद्धांत निरर्थक है। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति उस सिद्धांत के मूल में थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक 'अल हिलाल' निकाला था। उसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों को गैर-इस्लामिक परंपरा त्यागने को कहा। उन्होंने लिखा, 'यदि मजहब के कारण लड़ाइयां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि मजहब के अनुयायियों ने उसे समझने में गलती की है।'

स्वामी विवेकानंद सभी पंथों के एक ही परम तत्व सागर में विलीन होने की बात कहते थे, पर उनके अलग अस्तित्व के विरोध में नहीं थे। वह कहते थे, 'हम सभी उपासना पद्धतियों की महज सहन करने के पक्ष में नहीं हैं, अपितु हम उन सभी को सच्चा मानते हैं।' काश यह मजहबी कट्टरपंथियों को समझ आता। काश बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने मुक्ति संग्राम से ही सबक लेते कि किसी देश के बहुसंख्यकों द्वारा अपने अल्पसंख्यकों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किए जाने पर उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। यह सीख बांग्लादेश के बहुसंख्यकों ने बरती होती तो रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में 'आमार सोनार बांग्ला' आज सांप्रदायिकता की आग में न झुलस रहा होता। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, जहां अल्पसंख्यक न मिलें। कहीं धार्मिक अल्पसंख्यक मिलेंगे, कहीं भाषाई, कहीं जातीय। सवाल है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहां जाएं? बांग्ला लेखक कपिलकृष्ण ठाकुर के उपन्यास 'उजानतलीर उप कथा' में एक गीत का हिंदी भावार्थ है-स्वाधीन देश में मजहबी कट्टरता के कारण लोग पलायन करें, ऐसा सुना है क्या? बांग्लादेश में कभी 20 प्रतिशत से अधिक हिंदू थे। आज उनकी संख्या 7-8 प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कट्टरपंथी ताकतों की भागीदारी के आसार देखते हुए वहां हिंदुओं का भविष्य और अधिक स्याह नजर आने लगा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि मजहबी कट्टरता सबसे पहले लोकतंत्र को लील जाती है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ट्रंप-कमला के बीच रोचक मुकाबला

अरुणभ ठो

बाइडन द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने और कमला हैरिस का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करने से अमेरिका में चुनावी परिदृश्य बदलने लगा है

राजनीति में कब और कहां नए अध्याय या घटनाक्रम जुड़ जाएं, इसका कोई अनुमान नहीं लग सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब केवल तीन महीने शेष हैं। हाल की कुछ घटनाओं ने वहां के चुनावी परिदृश्य को बदल दिया है। गत दिनों डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुए हमले की तस्वीरों ने विश्वभर में उनके प्रति सहानुभूति जगाई। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव प्रचार एक पल के लिए रुकता नजर आया। ट्रंप की छवि एक हीरो की तरह उभरने लगी। उनके 'फाइट, फाइट, फाइट' के नारे लोगों की जुबान और कपड़ों पर छा गए। इस तरह चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि आगामी चुनाव एकतरफा हो सकता है।

राजनीति को अक्सर शह-मात का खेल कहा जाता है। अमेरिका में यह सच साबित प्रतीत हो रहा है। जो बाइडन द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने और कमला हैरिस का राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करने से अमेरिका में चुनावी परिदृश्य बदलने लगा है। कमला हैरिस की उम्मीदवारी ने चुनाव को रोचक बना दिया है। अब अमेरिका का चुनावी दृश्य पूरी तरह से बदल गया है। चुनावी संघर्ष फिर से बराबरी पर आ गया है। ट्रंप द्वारा कमला हैरिस पर की जा रही नस्लीय टिप्पणियों को न केवल अमेरिका, बल्कि पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। निःसंदेह अमेरिका जैसे विकसित और विविधतापूर्ण सोच वाले देश में एक पूर्व राष्ट्रपति या भावी उम्मीदवार से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। वैसे भी किसी को भी चुनावी प्रचार में या अन्य किसी भी कारण से किसी की पहचान पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ट्रंप इतनी जल्दी कैसे भूल गए कि उन्होंने कभी एशियन-अमेरिकन विरासत पर बल दिया था। यह सत्य है कि कमला हैरिस की जड़ें भारत और जमैका से हैं। इससे यह साफ दिख रहा है कि ट्रंप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मात्र एक पखवाड़े में ही उन्होंने चुनावी हवा का रुख अपने खिलाफ कर लिया है।

अमेरिका में ट्रंप की नस्लीय टिप्पणियां चुनावी मुद्दे के रूप में उभर रही हैं। बाइडन के चुनावी दौड़ से हटने को वह तख्तापलट कह रहे हैं और कमला हैरिस के बारे में यह तक कहने से नहीं चूकते कि वह अमेरिका में अपराध, अराजकता, अशांति और नरसंहार का कारण बनेंगी। ट्रंप के इन बयानों ने उनके प्रति उमड़ी सहानुभूति को कम किया है। कल तक जहां बाइडन की उम्र को लेकर टूंच सवाल उठाते थे, अब 78 वर्षीय ट्रंप और 59 वर्षीय कमला की उम्र चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि अमेरिका में कौन भारी पड़ता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बढ़ाने होंगे रोजगार के अवसर

'युवाओं में कौशल विकास की चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में डा. सुरजीत सिंह ने भारत में रोजगार सृजन करने की सरकार की मंशा की तरफ ध्यान इंगित किया है। भारत जैसे विकासशील देश में रोजगार की समस्या एक मुख्य समस्या बनी हुई है। भारत में विशेष तौर पर संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। अर्थात भारत में रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध होने के बावजूद भी बेरोजगारी एक मुख्य समस्या बनी हुई है। इसका मुख्य कारण है युवाओं में निम्न कौशल का होना है। अर्थात जो कौशल उद्योग जगत को चाहिए और जो कौशल हमारे युवाओं में है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए रोजगार के कई अवसर उपलब्ध होने के बावजूद उचित उम्मीदवार न मिलने के कारण वे पद खाली पड़े हैं। इस अंतर को पाटने के लिए भारत सरकार ने बजट में युवाओं में उचित कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। देश की शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका प्रदान किया जाएगा। अगर इन फैसलों का जमीन पर ठीक से क्रियान्वयन होता है तो इससे न केवल युवाओं में उच्च कौशल का विकास होगा, बल्कि उन्हें कुछ आय भी प्राप्त होगी। इसके साथ-साथ सरकार को एमएसएमई, स्टार्टअप और विनिर्माण क्षेत्रों में भी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो देश के युवाओं में उचित कौशल विकसित करके उन्हें रोजगार प्रदान करना एक अति अनिवार्य कदम होना चाहिए।

गुलशन स्वामी, फरीदाबाद

मेलबाक्स

भाग्य का खेल

कैसा यह भाग्य का खेल है कि कुछ ही घंटे के अंदर विनेश फोगाट का परम आनंद एक व्यथा में बदल गया। जिस प्रकार से वह शानदार फार्म में थीं, स्वर्ण पदक पर उनका ही नाम था। अगर विनेश ने पहले दिन अपना बजन नियंत्रण में रखा था तो दूसरे दिन भी ऐसा ही करना था। 2016 और 2020 के ओलिंपिक में शरीर ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन इस बार पेरिस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उनके और स्वर्ण पदक के बीच यह 100 ग्राम का अवरोध आ गया। अमेरिकी पहलवान सारा ने स्वर्ण पदक जीता है। वह पहले 55 किलो भारवर्ग में लड़ती थीं, अब 50 किलो में लड़ती हैं, लेकिन उन्होंने 50 किलो के लिए 2022 से तैयारी शुरू कर दी थी। इससे साफ पता चलता है कि लंबे संघर्ष और परिश्रम के बाद ही सफलता हासिल होती है। यह बेहद दुखद था कि इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा राजनीति की जा रही थी। चाहे जो भी हुआ हो इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विनेश एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और ओलिंपिक पदक न जीत पाने पर भी भारतीय कुश्ती में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। विनेश फोगाट कल भी बेमिसाल थीं, आज भी हैं और कल भी रहेंगी।

बाल गोविंद, नोएडा

निराश न हों विनेश फोगाट

खेलों के नियम होते हैं और इन नियमों का पालन करना हर खिलाड़ी के जरूरी होता है। आजकल पेरिस में ओलिंपिक चल रहा है। इसमें हर देश के खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतें। हमारे देश के खिलाड़ी भी इसमें पूरी मेहनत से डटे हुए हैं और मेडल भी जीत रहे हैं, लेकिन हमारे देश को एक निराशा भी हाथ लगी है, यह होन्हार पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलिंपिक में मात्र लगभग सौ ग्राम वजन बढ़ने के कारण रेसलिंग के फाइनल से बाहर होना है। अगर वह फीट रहतीं तो शायद गोल्ड मेडल जीत जातीं, लेकिन यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि फाइनल मुकाबले में वह नहीं खेल पाईं। विनेश निराश न हों, खेलों में ऐसा चलता ही रहता है, देश को अभी भी आप से उम्मीदें हैं कि आप भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करेंगीं, आप को निराश हो कर खेल से संन्यास लेने बारे नहीं सोचना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****